



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022025-260970  
CG-DL-E-13022025-260970

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]  
No. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2025/माघ 22, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025/MAGHA 22, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय )

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2025

मामला सं. सीबीडी (ओआई) – 04/2023

विषय: वियतनाम में उत्पन्न या निर्यात किए गए "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास" के आयात से संबंधित सब्सिडी विरोधी जांच।

फा.सं. 6/32/2023- डीजीटीआर: - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और रियायती वस्तुओं पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रह और धति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एंटी-सब्सिडी नियम' या 'नियम' (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड ("इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में संदर्भित) ने घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और एंटी-सब्सिडी नियमों के अनुसार टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित एक एंटी-सब्सिडी जांच शुरू करने के लिए

एक आवेदन दायर किया था या 'पीयूसी' या 'सब्जेक्ट गुड्स' या 'टीटीजी') जो वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है (इसके बाद इसे 'विषय देश' भी कहा जाता है)।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/32/2023-डीजीटीआर दिनांक 13 फरवरी 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए एंटी-सब्सिडी नियमों के नियम 6 के अनुसार संबंधित देश से पीयूसी के आयात की एंटी-सब्सिडी जांच शुरू की गई, (ग) सरकार ने संबंधित माल की किसी अभिकथित राजसहायता की सीमा और प्रभाव की सिफारिश करने तथा प्रतिकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि उद्धवण की जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने नियम 6 सुप्रा के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले वर्तमान एंटी-सब्सिडी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में वियतनाम के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने वियतनाम सरकार को स्थिति स्पष्ट करने और सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने के उद्देश्य से परामर्श के लिए आमंत्रित किया। परामर्श 26.12.2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें वियतनाम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

ग. प्राधिकारी ने 13 फरवरी 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें संबंधित काउंटी से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित सब्सिडी-विरोधी जांच शुरू की गई।

घ. प्राधिकारी ने दीक्षा अधिसूचना की एक प्रति भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य इच्छुक पार्टियों को भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया।

ङ. प्राधिकारी ने नियमों के नियम 7(3) के अनुसार आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबंधित देश की सरकारों को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से प्रदान की। आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रदान की गई थी, जहां भी अनुरोध किया गया था।

च. प्राधिकारी ने नियमों के नियम 7(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड, वियतनाम को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।

छ. भारत में विषय देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर देने की सलाह दें।

ज. जवाब में, विषय देश के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दर्ज करके जवाब दिया है:

- i. फ्लैट (वियतनाम) कं, लिमिटेड
- ii. फ्लैट (हांगकांग) कं, लिमिटेड

झ. प्राधिकारी ने भारत में संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी जिसमें नियमों के नियम 7(5) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी।

- i. मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड
- ii. स्वैलेक एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड

- iii. प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड
- iv. रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- v. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
- vi. वारी एनर्जीज लिमिटेड
- vii. एल्पेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- viii. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
- ix. टॉपसन एनर्जी लिमिटेड
- x. टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड
- xi. एम्बी फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड
- xii. नवितास ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. सोवा पावर लिमिटेड

अ. हालांकि, एंटी-डिपिंग जांच में अनंतिम निष्कर्ष जारी होने के बाद, निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं/संघों/आयातकों ने तत्काल जांच में अभ्यावेदन दिए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने उनके निवेदनों पर भी विचार किया है।

- i. नॉर्थ इंडियन मॉड्यूल निर्माता संघ ("एनआईएमएमए")
- ii. सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए)
- iii. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए सबमिशन का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।

ठ. डीजीसीआई एंड एस से अनुरोध किया गया था कि वे धायल अवधि के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात का लेनदेन-वार ब्यौरा और जांच की अवधि भी उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना करने और लेन-देन की विधिवत जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ड. उत्पादन की इष्टतम लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) और नियमों के अनुलग्नक- III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर भारत में संबंधित वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) तैयार किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम सब्सिडी विरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ढ. प्राधिकारी द्वारा आवेदक घरेलू उद्योग और नियांतकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का स्थल पर सत्यापन करके उस सीमा तक वास्तविक निरीक्षण किया गया था जिसे आवश्यक समझा गया था। वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, पर भरोसा किया गया है।

ण. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुक्कानों की समीक्षा में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।

त. इस जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, साक्ष्य के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली सीमा तक, वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार की गई हैं।

थ. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त गैर-गोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

द. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को गैर-सहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

ध. प्राधिकारी ने पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए समय प्रदान किया। हालांकि, किसी भी इच्छुक पार्टी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

न. प्राधिकारी ने उठाए गए सभी तर्कों और सभी इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, इस हद तक कि साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों की जांच की है, जो वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के निष्कर्षों का आधार बन गए हैं।

प. प्राधिकारी ने 29.01.2025 को सभी इच्छुक पार्टियों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण परिचालित किया। इच्छुक पार्टियों को 05.02.2025 तक प्रकटीकरण बयान पर अपनी टिप्पणी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

फ० प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पार्टीयों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों की संगत समझो गई सीमा तक जांच की है। कोई भी निवेदन जो केवल पिछले सबमिशन का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

भ० प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, इस हद तक कि साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं।

म० इस अधिसूचना में '\*\*\*' एक इच्छुक पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार विचार किया जाता है।

य० विषय-अन्वेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 US\$ = ₹ 83.52 है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और वस्तु

4. प्राधिकारी ने दीक्षा अधिसूचना के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया:

"3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% ट्रांसमिशन 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक नहीं है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड'

#### ग.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. किसी भी इच्छुक पक्ष ने पीयूसी पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

#### ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और इसी तरह के लेख के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

क. विचाराधीन उत्पाद 'टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहिष्णुता सहित) से अधिक नहीं है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड' वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यात किया जाता है

ख. बाजार की भाषा में उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास, हीट स्ट्रेंथ ग्लास आदि टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। लौह सामग्री को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ लेपित होने पर ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2% -3% बढ़ जाता है।

ग. विषयगत उत्पादों का आयात मुख्य रूप से 8 अंकीय स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है 70071900 यद्यपि इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है, जैसा कि आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया है कि आयात आंकड़ों से स्पष्ट अनुसार 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 उपशीर्षों में भी संबंधित वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से, यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण संघर्ष की परिस्थितियों में प्रबल होता है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं और संबंधित देश से आयातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और संबंधित देश से आयातित विषय वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और माल के बाजार और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में आने वाली वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। राजस्वाधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए नियमों के तहत 'वस्तु की तरह' माना जाना चाहिए।

### ग. 3 प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को शुरू करने के चरण में, टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहिष्णुता सहित) से अधिक नहीं थी और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक हो, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड।
8. पीयूसी को सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास, हीट स्ट्रेंबल ग्लास आदि जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। पीयूसी का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। लौह सामग्री को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ लेपित होने पर ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2% -3% बढ़ जाता है।
9. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में उल्लिखित कांच और कांच के बने पदार्थ श्रेणी में और सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. प्राधिकारी नोट करता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और संबंधित देश से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं सब्सिडी-रोधी नियमों के अनुसार संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की वस्तु की तरह हैं।

### घ. घरेलू उद्योग और स्थिति का दायरा

#### घ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

11. अन्य इच्छुक पार्टियों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

#### घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

क. वर्तमान आवेदन बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) द्वारा दायर किया गया है और वे भारत में संबंधित वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं।

ख. भारत में संबंधित वस्तुओं के पांच (5) अन्य ज्ञात उत्पादक हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबंधित देश में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातिक या भारत में संबंधित वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है।

#### घ.3 प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

13. सब्सिडी रोधी नियमों के नियम 2 (बी) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) 'घरेलू उद्योग' से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण रूप से ऐसी वस्तु के विनिर्माण में लगे हुए हैं और उससे संबंधित कोई कार्यकलाप है या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित राजस्वायता प्राप्त वस्तु के निर्यातिकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ लगाया जा सकेगा बाकी निर्माताओं का जिक्र करते हुए।

14. प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदन बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) द्वारा दायर किया गया है। यह आगे ध्यान दिया जाता है कि आवेदक उद्योग के अलावा, 4 अन्य उत्पादक गोर्विंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड और गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड हैं जिन्होंने पीओआई में उत्पादन शुरू कर दिया है।

15. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि आवेदक ने संबंधित देश से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह विषय देश में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातिक या भारत में संबंधित वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, आवेदक का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक एंटी-सब्सिडी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन एंटी-सब्सिडी नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

#### ड. गोपनीयता और विविध मुद्दे

##### ड.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

16. अन्य इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियाँ की हैं:

क. कि टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय एक दशक से अधिक समय से चल रहे हैं। यह लंबे समय तक निर्भरता घरेलू उद्योग के लिए दक्षता में सुधार और बाजार में बदलाव के अनुकूल होने के लिए प्रोत्साहन को कम करती है, प्रतिस्पर्धा के बजाय निर्भरता को बढ़ावा देती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत भी व्यापार उपायों के अनिश्चित विस्तार को हतोत्साहित करते हैं। इस तरह के लंबे उपाय बाजार की गतिशीलता को विकृत करते हैं और नवाचार को कम करते हैं, जबकि आयात पर निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं।

ख. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि 2017, 2021 और 2023 में की गई पिछली जांच में घरेलू उद्योग लगातार यह साबित करने में विफल रहा कि आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक नुकसान हुआ।

ग. इच्छुक पार्टियों ने 5 के बजाय 3 साल के लिए शुल्क लगाने का अनुरोध किया है क्योंकि यह घरेलू उद्योग की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाएगा। यह लंबे समय तक संरक्षणवाद को हतोत्साहित करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के अनुरूप होगा।

घ. एसोसिएशन के जवाबों को खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी द्वारा उनकी प्रस्तुतियों को ठीक से संबोधित करने की आवश्यकता है।

### ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

17. विविध प्रस्तुतियों के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण इस प्रकार हैं:

क. उपयोगकर्ता संघ द्वारा प्रस्तुति/भागीदारी के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि सचेत और रणनीतिक निर्णय के मामले के रूप में, उपयोगकर्ता संघ कभी भी अनुरोधित जानकारी प्रदान नहीं करते हैं या प्राधिकारी द्वारा जारी कानून/व्यापार नोटिस के तहत आवश्यक जानकारी फाइल नहीं करते हैं। चूंकि उनका प्रतिनिधित्व विधिक पेशेवर भी कर रहे हैं, इसलिए घरेलू उद्योग सहित अन्य इच्छुक पक्षों के साथ अन्याय होगा कि वे उनके उत्तर को स्वीकार करें अथवा उन्हें जांच में अगे प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति दें। यहां तक कि सुनवाई के बाद भी, किसी भी उपयोगकर्ता संघ ने अपने कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी को उनके निराधार निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

ख. मामलों के इतिहास के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि पिछले मामलों का इतिहास, वह भी, विभिन्न स्रोतों के खिलाफ, इस मामले के तथ्य के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक प्रासंगिकता नहीं है। प्राधिकारी को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सब्सिडी विरोधी शुल्क/एंटी-डिपिंग/सब्सिडी शुल्क के विस्तार के लिए मामला बनता है या नहीं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पिछले उपायों का वर्तमान मामले में कोई परिणाम नहीं है, यदि निर्यातकों को सब्सिडी मिल रही है, तो घरेलू उद्योग के पास उचित राहत के लिए देश के कानूनों के तहत उपाय लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि निर्यातकों को लाभ की प्राप्ति पर विवाद नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग को ऐसी पद्धतियों से संरक्षण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

ग. इच्छुक पक्षों के इस कथन के संबंध में कि पिछली जांचों में प्राधिकारी को कोई क्षति नहीं मिली है, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि चीन और मलेशिया के विरुद्ध पिछली जांचों की मात्र एक नज़र में, इच्छुक पक्षों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्राधिकारी ने सभी मामलों में क्षति पाई है। तथापि, मलेशिया के विरुद्ध प्राधिकारी को कोई पाटन नहीं मिला और इसलिए उसके विरुद्ध कोई शुल्क नहीं लगाया गया।

घ. भाग लेने के इच्छुक पाटयों के अधिकारों के हनन के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि एक बार सरकारी राजपत्र में दीक्षा अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद, यह माना जाता है कि सभी इच्छुक पाटयों को पर्याप्त रूप से सूचित कर दिया गया है।

ड. 5 के बजाय 3 साल के लिए शुल्क लगाने के अनुरोध के संबंध में, घरेलू उद्योग ने इच्छुक पार्टीयों को प्रस्तुत किया है कि वे 3 साल के लिए कर्तव्यों की सिफारिश करने के अपने दावे के समर्थन में एक भी कारण प्रदान करने में विफल रहे हैं और इसलिए, प्राधिकारी को इच्छुक पार्टीयों के ऐसे किसी भी निराधार और तर्कीन प्रस्तुतीकरण की अवहेलना करनी चाहिए।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

18. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, सब्सिडी रोधी नियमों के नियम 8 में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

गोपनीय जानकारी:

(1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) और नियम 19 के उप-नियम (3) में निहित किसी बात के बावजूद, नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी कोई जानकारी किसी अन्य पार्टी को ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्ष नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-दर (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना का आपूतकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने के लिए या तो अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकता है।

19. गोपनीयता के संबंध में प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि सभी इच्छुक पार्टियों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है।

20. यह तर्क दिया गया है कि एंटी-डंपिंग/सब्सिडी शुल्क एक दशक से अधिक समय से लागू है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि विषय जांच एक नई कार्यवाही है और इसमें पहले लगाए गए कर्तव्यों की निरंतरता शामिल नहीं है। प्राधिकारी ने यह जांच सब्सिडी रोधी नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए की है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी देश के निर्यातक अनुचित व्यापार व्यवहार में संलिप्त हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तो घरेलू उद्योग कानूनी सहारा और संरक्षण का पूर्णत हकदार है।

**च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण**

**च.1 अन्य इच्छुक पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियाँ।**

21. अन्य इच्छुक पार्टियों ने सब्सिडी योजनाओं और मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं।

क. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों का पर्याप्त विश्लेषण किए बिना जांच शुरू कर दी है। आवेदक ने तीन तत्वों के अस्तित्व को स्थापित नहीं किया जिसमें एक प्रतिदेय सब्सिडी शामिल है, अर्थात्, (ए) वित्तीय योगदान, (बी) लाभ, और (सी) विशेषता।

ख. आवेदक द्वारा कथित अधिकांश सब्सिडी बिना किसी वास्तविक साक्ष्य के सरल दावे हैं।

ग. प्राधिकारी को किसी भी उद्देश्य के लिए सब्सिडी योजनाओं और मार्जिन का विश्लेषण करने के लिए निर्यातिक द्वारा दायर सत्यापित डेटा का उपयोग करना चाहिए।

**च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ**

22. घरेलू उद्योग ने राजसहायता और राजसहायता माजन के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किए हैं।

क. इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि निर्यातकों/उत्पादकों/संबंधित देश में संबंधित वस्तुओं के उनके सहयोगियों को विभिन्न प्रतिदेय सब्सिडी कार्यक्रमों से लाभ हुआ है।

ख. वियतनाम में विषय उत्पाद में प्रयुक्त मशीनरी के लिए औसत उपयोगी जीवन 5 से 7 वर्ष है। निर्यात किए गए उत्पादों के लिए निविष्टियों पर आयात शुल्क में दी गई छूट तब तक प्रतिदेय नहीं है जब तक कि छूट केवल निर्यातित उत्पादों के उत्पादन तक ही दी जाती है। वियतनाम सरकार के पास निर्यात किए गए उत्पादों के लिए खपत किए गए इनपुट की पुष्टि करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। यदि ऐसी प्रणाली मौजूद नहीं है या प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जाती है, तो इससे छूट की पूरी राशि का प्रतिकार होगा।

ग. विषय देश की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है और न ही कोई सार्थक जानकारी प्रदान की है। केवल सरकार ही इस बात से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती है कि उक्त योजना प्रतिदेय है या नहीं। जवाब देने वाला निर्यातिक केवल यह जानकारी प्रदान कर सकता है कि कोई लाभ प्राप्त हुआ था या

नहीं। अन्य न्यायालयों में, जहां निर्यातिक देश की सरकार सहयोग नहीं करती है, जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करते हैं और योजनाओं की प्रतिवादीयता निर्धारित करते हैं।

घ. सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वियतनाम में विषयगत वस्तुओं के निर्यातिकों को कतिपय लाभ उपलब्ध हैं। वियतनाम की सरकार ने भाग लेने वाले निर्यातिकों को भी कुछ लाभ दिए हैं। घरेलू उद्योग विनियोग पूर्वक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे सभी योजनाओं के लाभों की गणना करें, भले ही वे इसके आवेदन में उनकी पहचान की गई हों या नहीं।

### च.3 गणना पद्धति

23. एएससीएम का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 1 के पैराग्राफ 1 के अनुसार प्राप्तकर्ता को लाभ की गणना के लिए दिशानिर्देश और कार्यप्रणाली प्रदान करता है और आगे प्रदान करता है कि प्राप्तकर्ता को लाभ की गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई भी विधि पारदर्शी और पर्याप्त रूप से समझाई जाएगी। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता को लाभ की गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी विधि को उनके राष्ट्रीय कानून या संबंधित सदस्य के कार्यान्वयन नियमों में प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक विशेष मामले में इसका आवेदन पारदर्शी और पर्याप्त रूप से समझाया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ (राजसहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और प्रतिशुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 में राजसहायता की मात्रा के निर्धारण की पद्धति निर्धारित की गई है। इस जांच में निर्धारण इन दिशानिर्देशों के अनुसार है।

#### च.3.1 याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

i. कार्यक्रम 1 और 2 (गैर-टैरिफ क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क छूट; मशीनरी और उपकरणों के आयात पर आयात शुल्क में छूट)

क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतिकरण

24. वियतनाम का आयात शुल्क छूट कार्यक्रम (गैर-टैरिफ क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क छूट) गैर-टैरिफ क्षेत्रों में निर्माताओं के लिए कर राहत प्रदान करता है, विशेष रूप से निर्यात प्रसंस्करण और विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में निर्यात-उन्मुख उद्यमों को लक्षित करता है। कार्यक्रम टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास जैसे निर्यात सामानों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है। मशीनरी और उपकरण कार्यक्रम के आयात पर आयात शुल्क छूट के तहत यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनियां मशीनरी, उपकरण, घटकों, भागों, कच्चे माल, विशेष वाहनों और विशिष्ट निर्माण सामग्री सहित शुल्क मुक्त पूंजीगत संपत्ति आयात कर सकती हैं।

25. गैर-आवर्ती, क्षेत्र-विशिष्ट लाभ का उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में कच्चे माल के साथ-साथ पूंजीगत संपत्ति आयात करने वाले निर्माताओं के लिए सरकारी राजस्व को छोड़कर औद्योगिक विकास का समर्थन करना है।

#### घ. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टीयों द्वारा प्रस्तुत करना

26. वियतनाम सरकार (जीओवी) ने प्रस्तुत किया है कि आयात और निर्यात शुल्क आयात और निर्यात शुल्क पर कानून द्वारा शासित होते हैं। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कानून संख्या 107/2016/क्यूएच13 और अन्य प्रासंगिक मार्गदर्शन सहित डिक्री और परिपत्र जारी किए हैं। यह निर्यात प्रसंस्करण उद्यमों के लिए एक प्रोत्साहन नीति है। ऐसे मामलों में जहां आयातित कच्चे माल का उपयोग निर्यात के लिए वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है, इनपुट को आयात शुल्क से छूट दी जाएगी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस योजना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह जांच की अवधि के दौरान चालू था। कानून संख्या 107/2016/QH13 अचल संपत्तियों के आयात पर प्रोत्साहन के लिए भी प्रदान करता है।

27. प्रतिभागी निर्यातिक ने अपने प्रत्युत्तर में इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का दावा किया है।

#### ग. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

28. वित्त मंत्रालय (एमओएफ) और एमओएफ के तहत वियतनाम सीमा शुल्क (जीडीवीसी) के सामान्य विभाग आयात और निर्यात शुल्क योजना का प्रबंधन करते हैं। आयात और निर्यात शुल्क 107/2016/QH13 पर कानून द्वारा शासित और विभिन्न फरमानों और परिपत्रों द्वारा समर्थित, यह प्रणाली सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, शुल्क छूट

और कर प्रशासन पर दिशानिर्देश प्रदान करती है। निर्यात किए गए सामानों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, आपूर्ति और घटकों पर छूट लागू होती है, जिसमें व्यवसायों को आयातित सामग्रियों की मात्रा और मूल्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। इस कार्यक्रम में निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर आयात शुल्क में छूट का प्रावधान है। प्राधिकारी नोट करता है कि जीडीवीसी द्वारा बनाए गए ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में कोई सबूत और विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित संपूर्ण कच्चे माल का शुल्क मुक्त निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

29. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि कानून संख्या 107/2016/QH13 भी निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है:

"11. निवेश पर कानून के नियमों द्वारा निर्धारित निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र इकाई की अचल संपत्ति के रूप में आयात, जिसमें शामिल हैं:

- क) मशीनरी और उपकरण; मशीनरी और उपकरणों की असेंबली या संचालन के लिए घटकों, भागों, स्पेयर पार्ट्स; मशीनरी और उपकरण, घटकों, भागों, या मशीनरी और उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स के निर्माण के लिए कच्चा माल;
- बी) एक तकनीकी लाइन में विशेष उपयोग वाले वाहन सीधे एक निर्माण परियोजना के लिए उपयोग किए जाते हैं;
- स) निर्माण सामग्री जिसे घरेलू रूप से उत्पादित नहीं किया जा सकता है।

इस खंड में विनिर्दिष्ट आयातों पर आयात शुल्क की छूट नई निवेश परियोजनाओं और विस्तार परियोजनाओं पर भी लागू होती है।

30. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करता है कि कार्यक्रम 'गैर-टैरिफ क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क छूट' में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात पर आकस्मिक है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।

31. 'मशीनरी और उपकरणों के आयात पर आयात शुल्क छूट' के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि कानून संख्या 107/2016/QH13 नई निवेश परियोजनाओं और विस्तार परियोजनाओं के लिए अचल संपत्तियों की शुल्क छूट भी प्रदान करता है। इस प्रकार, इस स्कीम में छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान किया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किए जाते हैं। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो ऊपर बताए गए विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।

ii. कार्यक्रम संख्या 3: कॉर्पोरेट आयकर में कमी:

क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतिकरण

32. इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी हाई फोंग सिटी टैक्स डिपार्टमेंट, वियतनाम है। यह कार्यक्रम नए निवेश करने के लिए कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर छूट और कटौती प्रदान करता है। इस योजना के अनुसार, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को 4 वर्षों के लिए 100% कॉर्पोरेट आयकर से छूट दी गई है और अगले 9 वर्षों के लिए देय कर में 50% की कमी की गई है। यह कंपनी द्वारा संचालित सभी गतिविधियों पर लागू होता है, और निर्यात प्रदर्शन, घरेलू वस्तुओं के उपयोग या विशिष्ट उद्योगों के संबंध में कोई विशिष्ट आवश्यकताएं मौजूद नहीं हैं। मुख्य शर्त यह है कि कंपनी को वियतनाम सरकार द्वारा नामित क्षेत्रों में काम करना चाहिए, जिससे यह योजना कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट हो जाती है।

33. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से राजसहायता की प्रति-निगरानी करने का अनुरोध किया है क्योंकि निर्यातक ने भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की बात स्वीकार की है।

ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

34. यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्यक्रम सरकार द्वारा परिभाषित कठिन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में समाजीकरण परियोजनाओं में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर छूट और कटौती प्रदान करता

है। विशेष रूप से, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को 4 साल के लिए कॉर्पोरेट आयकर से छूट दी जाती है और अगले 9 वर्षों के लिए देय कर में 50% की कमी से लाभ होता है। यह कंपनी द्वारा संचालित सभी गतिविधियों पर लागू होता है, और निर्यात प्रदर्शन, घरेलू वस्तुओं के उपयोग या विशिष्ट उद्योगों के संबंध में कोई विशिष्ट आवश्यकताएं मौजूद नहीं हैं। मुख्य शर्त यह है कि कंपनी को कठिन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के रूप में नामित क्षेत्रों में काम करना चाहिए।

35. सहायता की मात्रा कॉर्पोरेट आयकर पर कानून में उल्लिखित मानदंडों पर आधारित है। कार्यक्रम में भाग लेने वाली कंपनियों को प्राप्त लाभों का दस्तावेजीकरण करने के लिए कर रिटर्न जैसे रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम लाभ प्रदान करता है, कंपनियों को 4 वर्षों के लिए 100% कॉर्पोरेट आयकर से छूट देता है और बाद के 9 वर्षों के लिए 50% कर कटौती की पेशकश करता है। यह कार्यक्रम अभी भी संचालन में है। निर्यातक ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना स्वीकार कर लिया है।

#### ग. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

36. प्राधिकारी नोट करता है कि कार्यक्रम आयकर से छूट प्रदान करता है कॉर्पोरेट आयकर 14/2008 / QH12 (कानून 32/2013/QH13 और कानून 71/2014/QH13 द्वारा संशोधित) और 2000 में संशोधित विदेशी निवेश के कानून द्वारा शासित है। पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कंपनियों को 4 वर्षों के लिए कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) से पूर्ण छूट दी जाती है, इसके बाद अगले 9 वर्षों के लिए देय कर में 50% की कमी की जाती है। इस प्रकार, कार्यक्रम पूर्वामी राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है, जो अन्यथा देय है और लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम भी क्षेत्र विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट है क्योंकि यह प्रोत्साहित क्षेत्रों या प्रोत्साहित भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। निर्यातक ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।

#### iii. कार्यक्रम संख्या 4: भूमि और पानी के किराए की छूट और कमी

##### क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतिकरण

37. वियतनाम में वित्त मंत्रालय कानून संख्या 67/2014/QH13 को लागू करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है, जबकि स्थानीय कर प्राधिकारी भूमि किराया डेजियर संभालते हैं। पीओआई के दौरान, भूमि और पानी की सतह का किराया संग्रह डिक्री 46/2014/एनडी-सीपी द्वारा शासित किया गया था, जो वंचित क्षेत्रों में या महत्वपूर्ण निवेश के साथ परियोजनाओं के लिए किराए में छूट और कटौती प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, क्षेत्रीय और स्थानीय प्राधिकारी वियतनाम में विषय वस्तुओं के निर्माताओं को भूमि प्रदान करते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि भूमि पूर्व-निर्धारित दर पर प्रदान की गई थी, इसलिए खरीद मूल्य या भूमि मूल्य सही तस्वीर को प्रतिविवित नहीं कर सकता है।

##### ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

38. यह सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उद्यमों को भौगोलिक क्षेत्रों या विशेष रूप से कठिन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार उन कंपनियों के लिए छूट और भूमि किराए में कमी की नीति का अनुसरण करती है जिनके पास ऐसे क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भूमि किराए और पानी की सतह के किराए में छूट और कमी के हकदार संस्थाएं संबंधित डिक्री के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 में निर्धारित हैं। इस योजना के तहत, कर अधिकारी भूमि किराएदारों या पानी की सतह के किराएदारों द्वारा देय राशि और विशेष रूप से छूट या कमी की गई राशि का निर्धारण करेंगे। कराधान के प्रांतीय विभागों के निदेशक आर्थिक संगठनों, विदेशी संगठनों और व्यक्तियों के संबंध में छूट प्राप्त राशियों का निर्णय करेंगे। वित्त मंत्रालय भूमि किराए और पानी की सतह के किराए में छूट और कमी के लिए प्रक्रियाओं पर निर्देश देगा। यह खंड अनुच्छेद 15 परिपत्र संख्या 77/2014/टीटी-बीटीसी द्वारा भूमि किराए, पानी की सतह के किराए में छूट और कमी के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में विनियमित है। कर प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन को भूमि उपयोगकर्ता के वित्तीय दायित्वों के निर्धारण पर दस्तावेजों के स्वागत और हस्तांतरण के लिए प्रक्रियाओं पर कानून के नियमों के अनुसार संसाधित किया जाएगा। इस अनुच्छेद के खंड 3 में उल्लिखित आवेदन के अनुसार, कर प्राधिकारी प्रेषित भूमि किराया या पानी की सतह का किराया निर्धारित और तय करेगा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह कार्यक्रम अभी भी चालू है।

39. तथापि, निर्यातिक ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि विभिन्न कंपनियों पर लागू किराया गैर-तुलनीय है क्योंकि प्रत्येक कंपनी पर लागू किराया दीन्ह वू औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त स्टॉक कंपनी द्वारा मामला दर मामला निर्धारित किया जाएगा। दीन्ह वू औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त स्टॉक कंपनी न्यूनतम स्वीकार्य बेंचमार्क निर्धारित करेगी। निर्यातिक ने हालांकि कहा कि उक्त न्यूनतम स्वीकार्य बेंचमार्क का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दीन्ह वू औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त स्टॉक कंपनी की गोपनीय जानकारी है और अन्य कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। निर्यातिक ने प्रस्तुत किया कि हैफोंग पीपुल्स सरकार के पास दीन्ह वू औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त स्टॉक कंपनी की 25.1% इक्विटी होने के बावजूद, हैफोंग पीपुल्स सरकार उक्त कंपनी के दैनिक कार्यों में संलग्न नहीं है। इसलिए, निर्यातिक ने प्रस्तुत किया कि उन पर लागू किराया पूरी तरह से बाजार मूल्य पर आधारित है और इसलिए, इस योजना को किसी भी दृष्टिकोण से सम्बिंदी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

#### ब. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

40. प्राधिकारी सरकार द्वारा दायर प्रतिक्रिया से नोट करता है कि इस योजना के तहत, कर अधिकारी भूमि किराएदारों या पानी की सतह के किराएदारों द्वारा देय राशि और विशेष रूप से छूट या कमी की गई राशि का निर्धारण करेंगे। कराधान के प्रांतीय विभागों के निदेशक आर्थिक संगठनों, विदेशी संगठनों और व्यक्तियों के संबंध में छूट प्राप्त राशियों का निर्णय करेंगे। इसके अलावा, सरकार ने इस योजना के तहत संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातिकों द्वारा किसी लाभ की प्राप्ति से न तो इनकार किया है और न ही स्वीकार किया है। जीओवी ने भाग लेने वाले निर्माता से यह जानकारी एकत्र करने की सलाह दी है। यह आगे ध्यान दिया जाता है कि HEZA के माध्यम से दीन्ह वू-कैट है आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में सरकारी निरीक्षण और दिशा की एक महत्वपूर्ण डिग्री है, जो दीन्ह वू - कैट है इकोनॉमिक ज़ोन (DEEPC) का प्रबंधन करता है। GOV विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों (HEZA सहित) के माध्यम से किराये की छूट या कटौती जैसे भूमि संबंधी प्रोत्साहन सहित निवेश प्रोत्साहन को मंजूरी देता है और प्रदान करता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों (एचईजेडए सहित) के माध्यम से जीओवी, निवेश प्रोत्साहन को मंजूरी देने और देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें किराये की छूट या कटौती जैसे भूमि से संबंधित प्रोत्साहन शामिल हैं। इस प्रकार यह ध्यान दिया जाता है कि वियतनाम सरकार (जीओवी) भूमि-उपयोग मूल्य निर्धारण पर अधिकार का प्रयोग करना जारी रखती है, जिसमें सरकार से सीधे पट्टे पर ली गई भूमि के लिए पट्टे की दरों का निर्धारण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, निजी पार्टियों द्वारा उप-पट्टे पर दी गई भूमि पर प्रतिबंध बने हुए हैं, क्योंकि इन निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित भूमि उपयोग अनुबंध विशिष्ट सरकारी फरमानों के तहत स्थापित सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए, प्राधिकारी नोट करता है कि वियतनाम में भूमि उपयोग अधिकारों का अधिग्रहण बाजार संचालित सिद्धांतों द्वारा शासित नहीं है।

41. जबकि भाग लेने वाले निर्यातिक ने स्थानीय प्राधिकरणों के साथ अनुबंध प्रस्तुत किए हैं और ऐसे अनुबंधों के अनुसार भुगतान दिखाए हैं और यह तर्क दिया है कि निर्धारित दरें बाजार संचालित हैं, प्राधिकारी पूर्ण मूल्य निर्धारण तंत्र और दीन्ह वू औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त स्टॉक कंपनी के साथ अपने समझौते की प्रकृति पर अपनी प्रश्नावली के उत्तर में सरकार द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत करने के अभाव में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि संविदागत राशि बाजार दरें।

42. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करता है कि यह कार्यक्रम पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है। कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह क्षेत्र विशिष्ट है और कुछ प्रोत्साहित क्षेत्रों तक सीमित है। प्राधिकारी का मानना है कि इस सम्बिंदी कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग ज्यूटी लगाई जानी चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी सत्यापन योग्य जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी ने इस योजना के लिए नियम 7 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों का सहारा लिया है।

#### iv. कार्यक्रम संख्या 5: निवेश सहायता

##### क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतिकरण

43. वियतनाम में योजना और निवेश मंत्रालय निवेश 61/2020/QH14 पर कानून के तहत निवेश प्रोत्साहन का प्रबंधन करता है। यह योजना विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों के लिए लागू है। योग्य परियोजनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों में वे शामिल हैं, जो वित्तीय या रोजगार सीमा को पूरा करते हैं। नई और विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, खनिज खनन, वाणिज्यिक आवास और कुछ उत्पाद शुल्क-कर वाले सामानों को छोड़कर।

### ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

44. यह प्रस्तुत किया गया है कि कानून संख्या 67/2014/QH13 के तहत, वियतनामी सरकार उन कंपनियों को गैर-आवर्ती वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो दो तंत्रों के माध्यम से वंचित औद्योगिक पार्कों में स्थित हैं: आंशिक पूंजी निवेश सहायता और रियायती ऋण पूंजी। कार्यक्रम तकनीकी और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण या रियायती ऋण के माध्यम से अनुदान प्रदान करता है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित कंपनियों को लक्षित करता है। नई निवेश परियोजनाओं और विस्तार परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रत्येक प्रकार के प्रोत्साहनों का स्तर कराधान पर कानून, लेखांकन पर कानून और भूमि पर कानून के नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। ये लाभ खनिज खनन में निवेश पर परियोजनाओं, विशेष उत्पाद शुल्क पर कानून के अनुसार विशेष उत्पाद शुल्क के अनुसार विशेष उत्पाद शुल्क के अधीन विनिर्माण/माल / सेवाओं की विक्री में निवेश पर परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे, सिवाय ऑटोमोबाइल, विमानों और नौकाओं के विनिर्माण पर परियोजनाओं पर।

### ग. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

45. सरकार की प्रतिक्रिया से यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान, निवेश 61/2020/क्यूएच14 पर कानून के तहत निवेश प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है। कानून 61/2020/QH14 के तहत, सभी संस्थाएं निवेश प्रोत्साहन और सहायता के लिए पात्र हो सकती हैं, भले ही वे विदेशी निवेशक या घरेलू निवेशक द्वारा निवेश किए गए हों। जांच की अवधि के दौरान, निवेश प्रोत्साहन या सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने के मानदंड कानून 61/2020/QH14 (अनुच्छेद 15) में निर्धारित किए गए हैं। आगे यह नोट किया जाता है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की है कि यह योजना संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातिकों पर लागू नहीं है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि रिकॉर्ड पर सत्यापित आंकड़ों के अनुसार, सहयोगी निर्यातिक ने इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं उठाया है।

46. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करता है कि सरकार आर्थिक रूप से विकलांग भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित कंपनियों को वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है। नई निवेश परियोजनाओं और विस्तार परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रकार, यह योजना अनुदान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करती है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो ऊपर बताए गए विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। तथापि, रिकार्ड में रखे गए सत्यापित आंकड़ों के अनुसार, सहयोगी निर्यातिक ने इस स्कीम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। सभी गैर-सहयोगी निर्यातिकों के लिए मार्जिन नियम 7 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

### v. कार्यक्रम संख्या 6: वियतनाम विकास बैंक द्वारा निवेश क्रेडिट

#### क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतिकरण

47. वियतनाम में योजना और निवेश मंत्रालय निवेश 61/2020/QH14 पर कानून के तहत निवेश प्रोत्साहन का प्रबंधन करता है। ये प्रोत्साहन विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों पर लागू होते हैं। योग्य परियोजनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल हैं, वित्तीय या रोजगार सीमा को पूरा करना (उदाहरण के लिए, पूंजी में कम से कम VND 6,000 बिलियन, वार्षिक राजस्व में VND 10,000 बिलियन, या 3,000+ कर्मचारी)। नई और विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है, खनिज खनन, वाणिज्यिक आवास और कुछ उत्पाद शुल्क-कर वाले सामानों को छोड़कर। पात्रता परियोजना अनुपालन पर आधारित है, न कि निर्यात प्रदर्शन या आयातित वस्तुओं पर घरेलू उपयोग पर।

#### ख. वियतनाम सरकार/अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

48. यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य निवेश क्रेडिट पर डिक्री 32/2017 / एनडी-सीपी वियतनाम विकास बैंक (वीडीबी) द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले राज्य निवेश क्रेडिट पर नीति निर्धारित करता है। VDB एक पॉलिसी बैंक है जो राज्य के 100% स्वामित्व में है और इसका उद्देश्य राज्य नीति ऋण देना है। वीडीबी के ऋण कार्यों में विकास के लिए निवेश ऋण पर नीतियों को लागू करना शामिल है (विकास निवेश के लिए ऋण देना; निवेश के बाद समर्थन; निवेश क्रेडिट गारंटी); निर्यात ऋण पर नीतियों को लागू करना (निर्यात के लिए ऋण प्रदान

करना; निर्यात निवेश गारंटी देना; बोली लगाने की भागीदारी के लिए गारंटी और निर्यात अनुबंधों के कार्यान्वयन के लिए)। 15 मई, 2017 से, डिक्री 32/2017/एनडी-सीपी जारी करने के साथ, वीडीबी ने अब निर्यात क्रेडिट प्रदान नहीं किया है। सरकार के प्रस्तुतिकरण के अनुसार, वीडीबी ने केवल पीओआई के दौरान डिक्री 32/2017/एनडी-सीपी के अनुसार संलग्न निवेश ऋण उधार लेने के लिए पात्र परियोजनाओं की सूची पर परिशिष्ट के तहत विषयों को राज्य निवेश क्रेडिट प्रदान किया। सरकार ने आगे कहा है कि टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास उक्त सूचियों में नहीं आते हैं।

#### ग. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

49. प्राधिकारी नोट करता है कि 31 मार्च, 2017 को वियतनाम सरकार द्वारा जारी डिक्री संख्या 32/2017/एनडी-सीपी, राज्य निवेश क्रेडिट पर नीति की रूपरेखा तैयार करता है। डिक्री में एक परिशिष्ट शामिल है जिसमें निवेश ऋण के लिए पात्र परियोजनाओं की एक विस्तृत सूची का उल्लेख है। प्राधिकारी नोट करता है कि वियतनाम विकास बैंक समय-समय पर संशोधित उपरोक्त डिक्री के परिशिष्ट के तहत परिभाषित परियोजनाओं की सूची को वित्तीय लाभ प्रदान कर रहा है। इस प्रकार, यह योजना अनुदान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करती है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जो सूची में दिखाई देते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि उक्त परिशिष्ट में विषयगत वस्तुएं शामिल नहीं हैं और इसलिए वे वीडीबी द्वारा वित्तीय अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ काउंटरवेलिंग छूटी नहीं लगाई जानी चाहिए।

#### च.3.8 सब्सिडी मार्जिन

50. वर्तमान जांच में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	फ्लैट ग्लास वियतनाम	रेंज %	सब्सिडी की प्रकृति
प्रोग्राम नंबर 1	कच्चे माल पर आयात शुल्क में छूट	***%	0-5	निर्यात आकस्मिक सब्सिडी
प्रोग्राम नंबर 2	अचल संपत्तियों की खरीद पर आयात शुल्क में छूट	***%	0-5	घरेलू
प्रोग्राम नंबर 3	इनकम टैक्स छूट	***%	0-10	घरेलू
प्रोग्राम नंबर 4	छूट और भूमि और पानी के किराए में कमी	***%	0-5	घरेलू
प्रोग्राम नंबर 5	निवेश सहायता	-	-	घरेलू
प्रोग्राम नंबर 6	वियतनाम विकास बैंक द्वारा निवेश ऋण	-	-	घरेलू
	कुल	***%	0-10	घरेलू
	फ्लैट (वियतनाम) कं, लिमिटेड के लिए नेट काउंटरवेलिंग छूटी	***%	0-10	निर्यात आकस्मिक सब्सिडी का शुद्ध
	शेष	***%	0-10	

### छ. क्षति और कारण लिंक

#### छ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ।

51. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने क्षति और कारण लिंक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं।

क. जांच के तहत अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन की मात्रा लगातार बढ़ी, दावों को खारिज करते हुए कि आयात ने उत्पादन को दबा दिया। यह वृद्धि इंगित करती है कि घरेलू उद्योग आयात से कथित क्षति के बावजूद उत्पादन बढ़ाने में कामयाब रहा, यह सुझाव देता है कि आयात ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित नहीं किया।

ख. जबकि आयात की मात्रा में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें भी कुछ अवधियों के दौरान बढ़ीं, यह दर्शाता है कि आयात से मूल्य दमन नहीं हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति इस डेटा के साथ संरेखित नहीं है और अन्य अंतर्निहित कारकों को इंगित करती है।

ग. आयात के लिए जिम्मेदार क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है क्योंकि यह महत्वपूर्ण बाहरी कारकों, जैसे कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता, वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पर विचार करने में विफल रहता है। इन कारकों ने स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित किया।

घ. घरेलू उद्योग का नुकसान क्षमता से अधिक विस्तार जैसे फैसलों से होता है, जिसने उनके वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाला। इस विस्तार के परिणामस्वरूप उच्च मूल्यहास और व्याज लागत हुई, जिससे परिचालन अक्षमताएं बढ़ गईं। इन स्व-प्रवृत्त मुद्दों को आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ड. एनआईपी की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पूंजी नियोजित (आरओसीई) पर 22% रिटर्न अक्षय ऊर्जा उद्योग मानकों की तुलना में अत्यधिक है, जो आमतौर पर लगभग 14-15% होते हैं। इस तरह के कुलाएं गए बेंचमार्क क्षति मार्जिन को अतिरिंजित करते हैं, जिससे आयात से क्षति के बारे में अनुचित निष्कर्ष निकलता है। एनआईपी की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति में स्पष्टता और निरंतरता की कमी ने हितधारकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। एक मानकीकृत दृष्टिकोण निष्पक्षता को बढ़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शुल्क सिफारिशों यथार्थवादी और न्यायसंगत मूल्यांकन पर आधारित हों।

च. साक्ष्य यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि आयात क्षति का प्राथमिक कारण है। बाजार की गतिशीलता, जैसे कि मांग में उतार-चढ़ाव और बढ़ती इनपुट लागत, घरेलू उद्योग के वित्तीय परिणामों को निर्धारित करने में अधिक प्रभावशाली थे।

छ. घरेलू उद्योग की पुरानी उत्पादन तकनीक और अक्षम संचालन इसकी चुनौतियों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाए बिना, आयात की उपस्थिति के बावजूद, उद्योग की वित्तीय समस्याएं बनी रहेंगी।

ज. आयातित सौर ग्लास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का पालन करता है, जिसमें आईईसी (अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) जैसे प्रमुख प्रमाणन निकायों द्वारा स्थापित किए गए शामिल हैं। घरेलू उत्पादकों ने अभी तक अपने उत्पादों को इन बेंचमार्क के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं किया है, विशेष रूप से स्थायित्व, ऑप्टिकल स्पष्टता और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग प्रभावकारिता के संदर्भ में।

झ. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स का तर्क है कि कम गुणवत्ता वाले घरेलू ग्लास का उपयोग करने से समय के साथ उच्च रखरखाव लागत और दक्षता हानि हो सकती है, जिससे भारत के सौर क्षेत्र में विदेशी निवेश हतोत्साहित हो सकता है। आयातों पर यह निर्भरता प्राथमिकता का मामला नहीं है बल्कि दीर्घकालिक परियोजना व्यवहार्यता और निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

ज. आयातित बनावट टेम्पर्ड ग्लास नवीन विशेषताएं प्रदान करता है, जैसे कि बाइफेशियल प्रौद्योगिकी संगतता और उच्च तापीय स्थिरता, जो घरेलू निर्माता अभी तक दोहराने में सक्षम नहीं हैं। यह तकनीकी अंतर बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए मॉड्यूल के लिए आयात पर निर्भरता को और मजबूत करता है।

ट. इन विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए आर एंड डी में निवेश करने में घरेलू उद्योग की विफलता इस मुद्दे को बढ़ा देती है, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास के स्रोत के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता है।

ठ. घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्लास में गुणवत्ता के मुद्दे मॉड्यूल दक्षता से समझौता कर सकते हैं, ऊर्जा के नुकसान में वृद्धि कर सकते हैं, और फोटोवोल्टिक सिस्टम के समग्र जीवनकाल को कम कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए आयात अपरिहार्य हो जाता है।

ड. इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्थानीय ग्लास में गुणवत्ता भिन्नताओं के परिणामस्वरूप मॉड्यूल निर्माण के दौरान अस्वीकृति दर में वृद्धि हुई है, निर्माताओं के लिए परिचालन लागत बढ़ रही है और उत्पादन कार्यक्रम और गुणवत्ता बेंचमार्क बनाए रखने के लिए आयात पर निर्भरता को मजबूर किया गया है।

ढ. इच्छुक पार्टियों ने उन्नत सौर मॉड्यूल के लिए वैश्विक मानकों द्वारा आवश्यक सख्त विनिर्देशों को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादकों की अक्षमता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, आयातित ग्लास अक्सर 91% से अधिक संचरण दर प्राप्त करता है, जबकि घरेलू उत्पादक इन थ्रेसहोल्ड को लगातार पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे सौर पैनलों में प्रदर्शन के मुद्दे पैदा होते हैं।

## छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

52. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारण लिंक के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

क. घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की उपस्थिति के बावजूद, आयात पूरे बाजार पर हावी है। जांच की अवधि के दौरान विषय देश से आयात बाजार हिस्सेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा।

ख. राजसहायता प्राप्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं जो जांच की अवधि के दौरान काफी सकारात्मक है।

ग. विषय आयातों से घरेलू उद्योग के मूल्यों पर लगातार दबाव पड़ा है क्योंकि संपूर्ण आंग्ल अवधि के दौरान उनके मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम थे।

घ. जांच की अवधि में, संबंधित माल का भू-मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत से कम था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर मूल्य दबाव को दर्शाता है।

ड. राजसहायता प्राप्त आयातों का घरेलू उद्योग के मूल्यों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है।

च. भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा बहुत \*\*\*% कम है।

छ. राजसहायता प्राप्त आयातों के लगातार दबाव के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का पर्याप्त निपटान नहीं कर पाया है। नतीजतन, घरेलू उद्योग को माल जमा होने से बचने के लिए अपनी माल-सूची का निपटान करने के लिए नियंत्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ज. जांच की अवधि में, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगभग \*\*\* % की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को भी महत्वपूर्ण नकद नुकसान और \*\*\*% के नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा है। यह किसी भी मानकों से पर्याप्त है।

झ. घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि पहल के बाद, उनके नुकसान में काफी वृद्धि हुई और आयात में भी वृद्धि हुई।

ज. वर्तमान मामले में अंतर्रिम शुल्क लगाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग वांछित स्तर तक पहुंचने के अलावा अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।

ट. कथित उच्च रिटर्न के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 22% की वापसी डीजीटीआर की लगातार प्रथा रही है जिसे कई मामलों में उच्च अधिकारियों द्वारा भी बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, 22% का रिटर्न नियोजित पूंजी (कार्यशील पूंजी और अचल संपत्तियों) पर है जो उचित दिशानिर्देशों के साथ निर्धारित किया जाता है और एनआईपी पर पहुंचने के सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग ने यह भी

बताया कि 22% ROCE का मतलब आम तौर पर लागत पर \*\*\* से \*\*\*% लाभ होता है और कई मामलों में इससे भी कम होता है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा या असाधारण नहीं माना जा सकता। 22% के समर्थन में, घरेलू उद्योग ने ऐसे फैसले भी दिए हैं जिनमें अदालतों/न्यायाधिकरणों ने नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न को बरकरार रखा है।

- ठ. घरेलू उद्योग इस बात पर जोर देता है कि क्षति मापदंडों का विश्लेषण अलगाव में नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में मूल्य कम कटौती और मूल्य मंदी दोनों मौजूद हैं और इसलिए, एडी समझौते के अनुच्छेद 3.2 की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से पूरा किया जाता है। इसी तरह, एडी समझौते के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, घरेलू उद्योग इस बात पर प्रकाश डालता है कि सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, भले ही उनमें से सभी क्षति का संकेत न दें।
- ड. घरेलू उद्योग ने भी क्षति के सांख्यिकीय साक्ष्य प्रदान किए और प्रस्तुत किया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई स्थापित क्षमता को क्षति की अनुपस्थिति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि इच्छुक पार्टियों द्वारा दावा किया गया है। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया है कि उच्चतर उत्पादन, बिक्री और मांग के बावजूद माल-सूची में भारी वृद्धि हुई है, जो वियतनाम से संबंधित वस्तुओं के हानिकारक प्रभाव को दर्शाता है।
- ढ. आगे यह भी कहा जाता है कि रिकार्ड पर सत्यापित आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि हानियां, निवेश पर नकारात्मक लाभ, बढ़ी हुई माल-सूची और क्षमता उपयोग में कमी, बिक्री वसूली और हानियों में गिरावट, वित्तीय निष्पादन में गिरावट और बाजार हिस्सेदारी में कमी के कारण घरेलू उद्योग गंभीर रूप से पीड़ित है।
- ण. मांग और आपूर्ति के अंतर के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि भारतीय उत्पादक भारतीय मांग का \*\*\* % पूरा कर सकते हैं, लेकिन 2022 में एंटी-डंपिंग शुल्क बंद होने के बाद से डंप किए गए आयात के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त मॉड्यूल निर्माण क्षमताओं के बावजूद, घरेलू ग्लास उत्पादन अनिवार्य रूप से लगातार डंपिंग / सब्सिडी के कारण अलाभकारी कीमतों के कारण नहीं बढ़ा है।
- त. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि अनंतिम शुल्कों के उद्धरण से क्षमता विस्तार की योजनाओं में सुधार हुआ है। यह भी कहा गया है कि माननीय वित्त मंत्री का 2024 का बजट भाषण भी इन प्रयासों का समर्थन करता है। आगे यह भी उल्लेखनीय है कि देश में पर्याप्त घरेलू सौर ग्लास क्षमताओं के विद्यमान होने के कारण संबंधित वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क की छूट बंद कर दी गई है।
- थ. गुणवत्ता के दावों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उसके माल की गुणवत्ता आयातित वस्तुओं के बराबर है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ पक्षों द्वारा घटिया गुणवत्ता के दावों में तथ्यात्मक साक्ष्य की कमी है, क्योंकि अंतिम उत्पादों पर कोई सहायक डेटा या प्रभाव प्रदान नहीं किया गया है। इच्छुक पाटयों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि इच्छुक पाटयों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, उत्पाद से संबंधित नहीं हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि "ग्लास-टू-बैक शीट" से "ग्लास-टू-ग्लास" में संक्रमण, प्रौद्योगिकी ने मांग में वृद्धि की है और गुणवत्ता की चिंताओं से असंबंधित है। इसके अतिरिक्त, लेमिनेशन के दौरान चिपकाने से संबंधित मुद्दों, लेमिनेशन के दौरान ब्लास्टिंग, चिपकने वाली विफलता को कांच की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी इच्छुक पक्षकार ने यह दर्शनी के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुओं का उपयोग करने के कारण उनके मॉड्यूलों को उनके प्रयोक्ताओं द्वारा गुणवत्ता सूचकांक में डाउनग्रेड किया गया था।
- द. उपर्युक्त के अलावा, यह सूचित किया जाता है कि घरेलू उद्योग के विरुद्ध गुणवत्ता संबंधी दावे कुल बिक्री मात्रा के \*\*\* % से भी कम हैं, जो इसकी महत्वहीनता को दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी ने गुणवत्ता से संबंधित तर्कों को लगातार खारिज कर दिया है जब घरेलू और आयातित उत्पाद बाजार में प्रतिस्थापन योग्य हैं।

ध. उच्च मूल्यहास और व्याज लागत के दावों के संबंध में, घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि मूल्यहास और व्याज लागत दोनों कुल लागत का केवल \*\*\* % है, जो उद्योग के बड़े पैमाने पर नुकसान और नकद नुकसान के लिए अपर्याप्त है।

### छ.3 प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

53. इस संबंध में इच्छुक पाटयों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबंधित देश से राजसहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

54. सन्सिडी नियमों का नियम 13 क्षति के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

#### 13. क्षति का निर्धारण-

(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों की दशा में, अभिहित प्राधिकारी यह और निष्कर्ष देगा कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्कालिक क्षति होती है या उससे तात्कालिक क्षति होती है या उससे भौतिक क्षति होती है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में भौतिक रूप से बाधा आती है।

(2) उपनियम (3) के अधीन क्षति का पता लगने के सिवाय, अभिहित प्राधिकारी उद्योग की स्थापना के लिए क्षति, क्षति की धमकी, सामग्री मंदता और राजसहायता प्राप्त आयात और क्षति के बीच आकस्मिक संबंध का अवधारित करेगा, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुलग्नक 1 में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए।

(3) अभिहित प्राधिकारी, अपवादिक दशाओं में, क्षति के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष दे सकेगा, जहां घरेलू उद्योग का पर्याप्त भाग घायल न हो यदि-

- (i) राजसहायता प्राप्त आयातों का पृथक बाजार में संकेन्द्रण हो, और
- (ii) राजसहायता प्राप्त आयातों से उत्पादकों को ऐसे बाजार में उत्पादित लगभग संपूर्ण उत्पादन की क्षति हो रही है।

55. गैर-हानिकारक मूल्य के प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रतिलाभ से संबंधित मुद्दों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपनी सभी जांचों में नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिलाभ का लगातार उपयोग किया है और प्राधिकारी की संगत प्रथा से विचलन करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है जिसे विगत में न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा भी सही ठहराया गया है।

56. गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि किसी भी इच्छुक पक्ष ने घरेलू उद्योग द्वारा विशिष्ट गुणवत्ता विनिर्देशों को प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाई से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है। कुछ इच्छुक पार्टियों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं से संबंधित गुणवत्ता के मुद्दों को बताते हुए बैठक के ईमेल संचार और मिनट प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग ने ईमेल संचार और ग्राहकों के साथ बैठक के मिनट द्वारा समर्थित दावों का खंडन किया है। प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान गुणवत्ता को पूरा न करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई क्षतिपूत की भी जांच की और इसे नगण्य पाया गया। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कुल गुणवत्ता दावे उनकी कुल विक्री के \*\*\* % से कम हैं।

57. यह ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन और वियतनाम दोनों से हानिकारक डंपिंग के संबंध में एक समानांतर जांच की है, जिसमें जांच की अवधि वर्तमान जांच में विचार की गई अवधि यानी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के समान थी। प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि उक्त निष्कर्षों में चीन के साथ-साथ वियतनाम से हानिकारक आयातों के संबंध में सकारात्मक निर्धारण किया गया है। उसमें किया गया दृढ़ संकल्प यहां भी प्रासंगिक है।

58. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इच्छुक पाटयों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण के तहत इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।

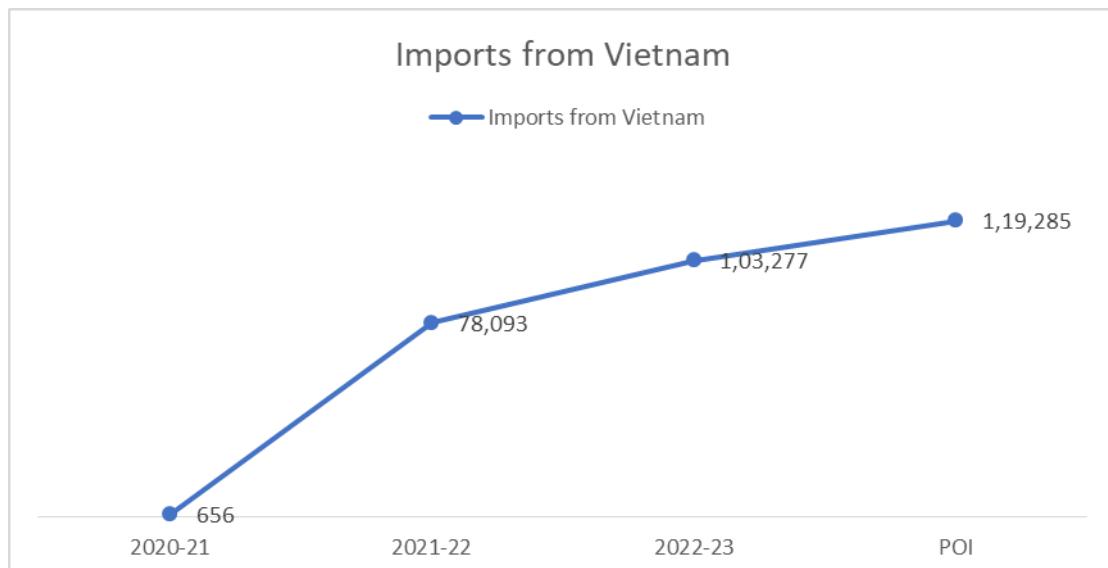
## सब्लिडी वाले आयात का मात्रा प्रभाव

### छ.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

59. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
विषय देश से आयात	एमटी	656	78,093	1,03,277	1,19,285
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,58,144	1,20,343	2,92,247	6,76,269
कुल आयात	एमटी	1,58,799	1,98,436	3,95,524	7,95,555
कुल आयात में आयात का % हिस्सा					
विषय देश से आयात	%	0.41%	39.35%	26.11%	14.99%
अन्य देशों से आयात	%	99.59%	60.65%	73.89%	85.01%
घरेलू विक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	188
अन्य उत्पादकों की विक्री	एमटी	-	-	-	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित				100
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	203	411
मांग में हिस्सेदारी					
विषय देश से आयात	अनुक्रमित	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	9,950	7,766	4,429
अन्य देशों से आयात		***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	64	91	104
कुल आयात		***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	104	123	122
घरेलू विक्री		***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	53	46
अन्य उत्पादकों की विक्री		0	0	0	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित				100
उत्पादन-पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	129	209
विषय देशों से आयात के संबंध में					
खपत	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	9,944	7,761	4,427

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन-पीयूसी	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	10,060	12,193	8,716



60. पैरा 40 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मात्रा से संबंधित मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित नोट करता है:

क. देशों (चीन और वियतनाम) से आयात में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2020-21 में 29,980 मीट्रिक टन से शुरू होकर, वे पीओआई (जांच की अवधि) के दौरान बढ़कर 779,017 मीट्रिक टन हो गए।

ख. वियतनाम का योगदान: वियतनाम से आयात वर्ष 2020-21 में 656 मीट्रिक टन से बढ़कर POI में 119,285 मीट्रिक टन हो गया, जो वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के बीच उच्चतम स्पाइक है।

ग. कुल आयात: संबंधित देश से आयात में वृद्धि को दर्शाते हुए, कुल आयात 2020-21 में 158,799 मीट्रिक टन से बढ़कर POI में 795,555 मीट्रिक टन हो गया, जो चीन और वियतनाम से आयात की ओर बदलाव का संकेत देता है।

घ. घरेलू उद्योग की विक्री: घरेलू उद्योग की विक्री की मात्रा पहले तीन वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रही, \*\*\* मीट्रिक टन से \*\*\* मीट्रिक टन के बीच और पीओआई के दौरान \*\*\* मीट्रिक टन तक बढ़ गई।

ड. अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्री: 2020-21 से 2022-23 तक अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए कोई विक्री दर्ज नहीं की गई। पीओआई के दौरान \*\*\* एमटी की विक्री की गई थी।

च. कुल मांग/खपत: समग्र बाजार मांग या खपत पूरी अवधि में ऊपर की ओर रही है, जो वर्ष 2020-21 में \*\*\* MT से बढ़कर POI के दौरान \*\*\* MT हो गई है, जो बाजार गतिविधि में वृद्धि का संकेत देती है।

छ. क्षति की जांच अवधि के दौरान खपत और उत्पादन के संबंध में आयात में कई गुना वृद्धि हुई है।

### छ.3.3 सब्सिडीकृत आयातों का मूल्य प्रभाव

61. नियमों के अनुलग्नक II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर सब्सिडी वाले आयात के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में इस तरह के उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी वाले आयात द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कम कटौती की गई है, या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को

काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा।

क) मूल्य में कटौती

62. जांच की अवधि के लिए आयातों के उत्तरार्द्ध मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की निवल विक्री वसूली की तुलना करके मूल्य अंडरकटिंग का निर्धारण किया गया है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
लैंडेड वैल्यू	रु./एमटी	65,191	50,435	44,181	40,265
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	77	68	62
घरेलू विक्री मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	113	95
मूल्य अंडरकटिंग	रु./एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	39	61	33
मूल्य अंडरकटिंग%	%	***	***	***	***
मूल्य अंडरकटिंग%	श्रेणी	नेगटिव	10-20	20-30	10-20

यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे।

ख) मूल्य दमन/अवसादन

63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या राजसहायता प्राप्त आयात घरेलू मूल्यों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव मूल्यों को काफी हद तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, धृति की अवधि के दौरान लागत और मूल्यों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई थी

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
विक्री की लागत घरेलू	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	119	105
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	111	93
लैंडेड प्राइस	₹/एमटी	65,191	50,435	44,181	40,265
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	77	68	62

64. प्राधिकारी उपर्युक्त से नोट करता है कि आयात का भू-मूल्य धृति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम था।

65. जांच की अवधि के दौरान, संबंधित वस्तुओं का अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग की विक्री लागत और इसके घरेलू विक्री मूल्यों से कम रहा। इसने घरेलू उद्योग को विक्री की लागत के अनुरूप अपनी कीमत रखने से रोक दिया। अत यह नोट किया जाता है कि आयातों ने मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हो सकती थी। इस प्रकार, आयातों का घरेलू उद्योग के मूल्यों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है।

### छ.3.4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

66. सब्सिडी विरोधी नियमों के लिए आवश्यक है कि क्षति के निर्धारण में संबंधित वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी वाले आयात के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ समीक्षा शामिल होगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर राजसहायता प्राप्त आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार शेयर उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, सब्सिडी के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

67. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे -

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
क्षमता (मीट्रिक टन)	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	128	232
अपेक्षा होना	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	सूचकांक	100	120	203	411
कुल उत्पादन (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	सूचकांक	100	115	125	199
केवल उत्पादन पीयूसी (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	129	209
क्षमता उपयोग (%)	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	98	86
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	188
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	153	210	271
मांग/उपभोग	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	203	411

68. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षति की जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग संस्थापित क्षमता का \*\*\* % था। इसका अर्थ यह है कि संपर्क वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद संस्थापित क्षमता का लगभग \*\*\* % अप्रयुक्त रहा।

ख. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री विषय वस्तुओं की कुल मांग की तुलना में नगण्य (लगभग \*\*\* %) है।

ग. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अन्य उत्पादकों के पास \*\*\* एमटी की संयुक्त क्षमता है। आवेदक उद्योग के साथ भारत में कुल उपलब्ध क्षमता इस प्रकार है:

विवरण	क्षमता	बिक्री	आयात - कुल	कुल मांग
उत्पादन (एमटी)				
आवेदक (मीट्रिक टन)	***	***		
गोबिंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमटी)	***	***		
त्रिवेणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (एमटी)	***	***		
विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (एमटी)	***	***		
गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (एमटी)	***			
इमर्ज ग्लास (MT)	***			
कुल (मीट्रिक टन)	***	***	795,555	***

घ. उपरोक्त से, यह नोट किया गया है कि वर्तमान में भारतीय उत्पादकों के पास भारतीय मांग का लगभग \*\*\* % है। इसके अलावा, जैसा कि भारतीय उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ अन्य उत्पादकों ने एंटी-डंपिंग-शुल्कों की समाप्ति के बाद चीन से आयात की आमद के कारण अपनी मशीनरी की स्थापना में देरी की है।

#### ii) मार्केट शेयर

69. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई थी:

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	188
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	0	0	0	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-	-	-	100
कुल भारतीय बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	225
विषय देश से आयात	एमटी	656	78,093	1,03,277	1,19,285
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	11,912	15,753	18,195
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,58,144	1,20,343	2,92,247	6,76,269
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	76	185	428
कुल आयात	एमटी	1,58,799	1,98,436	3,95,524	7,95,555
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	249	501
भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	203	411
बाजार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	53	46

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
अन्य उत्पादक उद्योग	%-				***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित				100
भारतीय निर्माता	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	53	55
विषय आयात	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	9,950	7,766	4,429
अन्य देश आयात	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	64	91	104

70. यह देखा गया है कि मांग के लगभग \*\*\* % की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल \*\*\* % है।

iii. सूची

71. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
समापन इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
औसत इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	104	289	405

72. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत सूची में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान औसत इन्वेंट्री सबसे अधिक थी।

(iv) निवेशित पूँजी पर लाभ/हानि, नकद लाभ और प्रतिफल।

73. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत (घरेलू)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	119	105
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	111	93
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-56	-236	-269
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-61	-253	-505
नकद लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-43	-316	-633
निवेश की वापसी	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-83	-269	-453

74. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि:

- क. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में वर्ष 2021-22 और 2022-23 की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है
- ख. पीओआई के दौरान, घरेलू उद्योग की लागत में गिरावट आई, हालांकि, बिक्री मूल्य में गिरावट तेज थी। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि इससे उनकी स्थिति और खराब हो गई है।
- ग. आवेदक को हानि और नकद हानि हुई है और जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल भुगतान पड़ रहा है।

(v) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

75. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	172	177
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	153	118	115
वेतन और मजदूरी	₹/संख्या	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	122	68	65
प्रति दिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/दिन	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	129	209
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	75	118

76. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू उद्योग ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि की है। यह भी नोट किया गया है कि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

77. कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन में लगभग \*\*\* % की कमी आई है अर्थात् आधार वर्ष में 100 अनुक्रमित प्वाइंट्स से जांच की अवधि में \*\*\* इंडेक्स्ड प्वाइंट हो गया है, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार इस पर राजस्वायता के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

(vi) विकास

व्यक्तियों	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
मांग – एमटी	%	-	***	***	***
उत्पादन – एमटी	%	-	***	***	***

घरेलू बिक्री - एमटी	%	-	***	***	***
बाजार में हिस्सेदारी%	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री - रु/एमटी	%	-	***	***	***
लाभ/हानि - रु/एमटी	%	-	***	***	***
नकद लाभ - रु/एमटी	%	-	***	***	***
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल %	%	-	***	***	***

78. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान संबंधित वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। जांच की अवधि में लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय काफी नकारात्मक थी जो जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को दर्शाती है।

**(vii) पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता**

79. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसे भारी नुकसान हुआ है और नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ रहा है। ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन (EBIDTA) से पहले की कमाई क्षति की अवधि में लगातार खराब हुई है और नकारात्मक बनी हुई है। आवेदक ने आगे प्रस्तुत किया है कि नकारात्मक ईंवीआईडीटीए से पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर रहा है और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

**(viii) सब्सिडी का मार्जिन**

80. राजसहायता का माजन इस बात का सूचक है कि राजसहायता प्राप्त आयातों से घरेलू उद्योग को किस सीमा तक क्षति हो सकती है। सब्सिडी मार्जिन वियतनाम के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

**घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

81. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपने मूल्यों में लाभकारी स्तर तक वृद्धि नहीं कर पाया है। आयात ने घरेलू उद्योग को लागत से कम मूल्य पर माल बेचने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा, कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी भी कम हुई है और घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग हुआ है। इस प्रकार, वियतनाम से विषयगत आयातों ने घरेलू उद्योग के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

**सामग्री क्षति पर निष्कर्ष**

82. विषय देश से विषयगत वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य प्रभावों तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव की जांच करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के पाठित आयातों में समग्र रूप से काफी वृद्धि हुई है। जहां तक संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात के कारण मूल्य प्रभाव का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें दब रही हैं/कम हो रही हैं। भू-मूल्य की घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्यों से तुलना करने से भी घरेलू उद्योग को क्षति का पता चलता है। घरेलू उद्योग पर राजसहायता प्राप्त आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लाभ, निवेश पर आय तथा नकदी प्रवाह के संबंध में निष्पादन नकारात्मक रहा। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

**ज. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण.**

83. घरेलू उद्योग के मूल्यों पर राजसहायता प्राप्त आयातों की हानि, मात्रा और मूल्य प्रभाव की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध राजसहायता प्राप्त आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

**क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत**

84. यह नोट किया गया है कि चीन को छोड़कर गैर-विषयक देशों से आयात मात्रा के लिहाज से नगण्य है। यह ध्यान दिया जाता है कि चीन के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच चल रही है। इसलिए, क्षति के लिए तीसरे देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

**ख. मांग में संकुचन**

85. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान विषय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंची है।

**ग. खपत का पैटर्न**

86. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत पद्धति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**घ. प्रतियोगिता की शर्तें**

87. प्राधिकारी नोट करता है कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियों का कोई सबूत नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा किए गए नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

**ड. प्रौद्योगिकी में विकास**

88. प्राधिकारी नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं किया गया है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता था।

**च. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन**

89. ऊपर जांच की गई क्षति सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति का श्रेय घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को नहीं दिया जा सकता।

कारण लिंक स्थापित करने वाले कारक

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति दर्शाता है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है।

- आयात निरपेक्ष रूप से बढ़े हैं और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। देश में क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद आयात में वृद्धि हुई है।
- विषय आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है और पीओआई में बिक्री की लागत से भी कम है और इससे मूल्य में कमी आई है।
- क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की इन्वेंटरी बढ़ रही है और पीओआई में काफी वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूँजी पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

91. उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित देशों से भारत में पीयूसी के बढ़ते हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। विषय देशों में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के राजसहायता प्राप्त आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध है।

**झ. क्षति मार्जिन की भयावहता**

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए अहानिकारक मूल्य निर्धारित किए हैं। विचाराधीन उत्पाद का अहानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाते हुए निर्धारित किया गया है। क्षति माजन की गणना करने के लिए संबंधित देश से अवतरण मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि में कम्बे माल के

सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूँजी (यानी औसत शुद्ध कुल्हाड़ी वाली संपत्ति और औसत कार्यशील पूँजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुँचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा था।

93. सहकारी निर्यातकों के लिए उत्तराई तक की कीमत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबंधित देश के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरण मूल्य निर्धारित किया है।

94. उत्तराई तक के मूल्य और उपरोक्तानुसार निर्धारित अहानिकर मूल्य के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति माजन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

निर्माता	लैंडेड वैल्यू (यूएसडी/एमटी)	एनआईपी (यूएसडी/एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
वियतनाम					
फ्लैट (वियतनाम) कंपनी, लिमिटेड/फ्लैट (हांगकांग) कं पनी	***	***	***	***	50-60
अन्य	***	***	***	***	50-60

### ज. भारतीय उद्योग के मुद्दे

#### ज.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

95. अन्य इच्छुक पार्टियों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं।

क. सौर ग्लास पर एंटी-सब्सिडी शुल्क सौर मॉड्यूल निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत में काफी वृद्धि करेगा, विशेष रूप से उन्नत फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों के लिए आयातित बनावट वाले टेम्पर्ड ग्लास पर निर्भर हैं। लागत में यह वृद्धि न केवल भारत की सौर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगी बल्कि राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को भी धीमा कर देगी।

ख. डाउनस्ट्रीम उद्योगों का तर्क है कि घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में कम प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के कारण उच्च लागत से सौर ऊर्जा को अपनाना कम हो सकता है, जिससे भारत अपनी हरित ऊर्जा पहल में और अधिक निराश हो सकता है।

ग. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कर्तव्यों का प्रभाव अनंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा इंगित किए गए प्रभाव से बहुत अधिक है। उनके द्वारा प्रस्तुत गणना के अनुसार, शुल्कों का प्रभाव वियतनाम से लगभग 3% और चीन से 6% होगा।

#### ज.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

96. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं।

क. घरेलू उद्योग में भारतीय मांग के लगभग \*\*\* % को पूरा करने की क्षमता है।

ख. यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के अलावा, पांच और उत्पादकों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए हैं।

ग. यदि मौजूदा स्थिति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने परिचालन और भारत को स्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और यह एक बार फिर आयात पर निर्भर हो जाएगा।

घ. बढ़ते व्यापार घाटे के प्रकाश में, घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर अधिक भरोसा करना महत्वपूर्ण है। शुल्क लगाने से भुगतान खाते के संतुलन के पक्ष में निवर्तमान विदेशी मुद्रा के संरक्षण की अनुमति मिलेगी।

ङ. सौर मॉड्यूल की लागत की तुलना में विषयगत वस्तुओं पर सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा।

च. चूंकि बाजार में पहले से ही छह खिलाड़ी हैं और कुछ और उत्पादन शुरू करने वाले हैं, इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में कोई एकाधिकार नहीं है और उपयोगकर्ताओं के पास घरेलू बाजार में भी पर्याप्त स्रोत होंगे।

छ. विचाराधीन उत्पाद का आयात अन्य स्रोतों से भी उचित मूल्य पर किया जा सकता है और इसलिए प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ज. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि सौर प्रकाशवोल्टीय पैनलों/मॉड्यूल निर्माताओं के पास 40% बीसीडी है और मॉड्यूल निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) का समर्थन है। यह सौर मॉड्यूल निर्माताओं को चीन और अन्य देशों से कम कीमत के आयात से सुरक्षा प्रदान करता है। यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तुएं सौर मॉड्यूल की लागत का बहुत छोटा हिस्सा है। अत अंतिम उत्पाद पर सब्सिडी-रोधी शुल्कों का कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

झ. शुल्कों के प्रभाव के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पीओआई में प्रचलित लागतों के आधार पर मॉड्यूल लागत पर विषयगत वस्तुओं पर शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा। विद्युत की प्रति यूनिट लागत पर प्रभाव के संदर्भ में, विषयगत वस्तुओं पर शुल्कों का प्रभाव बहुत कम होगा। इस प्रकार, संबंधित वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्कों का प्रभाव या तो अस्तित्वहीन है या बहुत नगण्य है।

ज. घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सब्सिडी शुल्क एक महत्वपूर्ण घटक के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और विदेशी मुद्रा आउटगो को बचाने और रोजगार पैदा करने के अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए, शुल्क भारतीय उपयोगकर्ताओं के हित में हैं।

### ज.3 प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

97. प्राधिकारी इस बात को रेखांकित करता है कि सब्सिडी रोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य सब्सिडी के अन्यायपूर्ण व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को सुधारना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। सब्सिडी-रोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य संबंधित देश से मनमाने ढंग से आयातों में कटौती करना नहीं है। बल्कि, यह सब्सिडी की क्षति और दोनों के बीच कारण लिंक के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और एक स्तर के खेल को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी स्वीकार करता है कि सब्सिडी विरोधी कर्तव्यों की उपस्थिति भारत में उत्पाद के मूल्य स्तरों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लागू करने से सुरक्षित रहेगा। घटती प्रतिस्पर्धा से दूर, सब्सिडी-विरोधी उपायों को लागू करने से सब्सिडी प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकने का कार्य किया जाता है। यह विषय वस्तुओं के व्यापक चयन के लिए उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, एंटी-सब्सिडी शुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष-व्यापार प्रथाओं का एक सूत्रधार है।

98. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी इच्छुक पाटयों से विचार आमंत्रित करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/नियर्तिकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पण्डारकों को उनके प्रचालनों पर सब्सिडी रोधी शुल्क के

संभावित प्रभाव सहित चल रही जांच से संबंधित संगत सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए आथक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

99. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूतकर्ताओं द्वारा आपूत किए गए उत्पाद की अदला-बदली क्षमता, स्वोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर राजसहायता-रोधी शुल्क के प्रभाव, सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने अथवा विलंब होने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी थी।

100. प्राधिकारी नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं आया है या आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, किसी भी पक्ष ने लागू कर्तव्यों के प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। हितधारकों की भागीदारी और साक्ष्य की कमी प्राधिकारी की स्थिति को रेखांकित करती है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी विरोधी उपायों की आवश्यकता को पुष्ट करती है।

101. तथापि, प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्कों के संभावित प्रभाव का अनुमान निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध कराया है।

व्यक्तियों	हवाला	यूआएम	कुल धनराशि
एमआईसी पर आधारित 540 डब्ल्यूपी सौर मॉड्यूल की कीमत) सौर सेल	ए	रु./मॉड्यूल	***
M10 सौर कोशिकाओं पर आधारित 540 Wp सौर मॉड्यूल में उपयोग किए जाने वाले विषय सामान	बी	किग्रा/मॉड्यूल	***
विषय वस्तुओं की कीमत - लेपित	सी	रु./किग्रा.	***
M10 सौर कोशिकाओं पर आधारित 540 Wp सौर मॉड्यूल में निर्मित विषय वस्तुओं की लागत	डी=सी*बी	रु/एमटी	***
मॉड्यूल में विषय वस्तुओं की % लागत	ई=डी/ए	%	***
संबंधित वस्तुओं पर 5% सब्सिडी विरोधी शुल्क के कारण मॉड्यूल पर अतिरिक्त लागत	एफ=डी*5%	रु/एमटी	***
मॉड्यूल में सब्जेक्ट गुड्स की कुल लागत सब्सिडी विरोधी शुल्क जोड़ना	जी=डी+एफ	रु/एमटी	***
मॉड्यूल में विषय वस्तुओं की % लागत	एच=जी/ए	%	***
सब्सिडी रोधी कर्तव्यों के कारण प्रति सौर मॉड्यूल पर अतिरिक्त प्रभाव	आई=एफ/ए	%	0.50%

102. उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण से प्राधिकारी नोट करता है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर सब्सिडी विरोधी शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा।

103. उपयोगकर्ताओं पर कर्तव्यों के उच्च प्रभाव के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि उपयोगकर्ताओं ने कोई सबूत नहीं दिया है कि यह उनके वित्तीय प्रदर्शन या अंतिम उपभोक्ता पर कर्तव्यों के प्रभाव को कैसे प्रभावित करेगा। उनके दावे को साबित करने के लिए कोई विश्वेषण/डेटा/कार्य भी प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रयोक्ता संघ ने उच्चतर प्रभाव दर्शने के लिए तालिका में केवल निम्न भू-अवतरण मूल्य को प्रतिस्थापित किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी क्षति जांच अवधि के दौरान प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रभाव नहीं दिखाया।

104. प्राधिकारी नोट करता है कि सब्सिडी विरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। अत शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

### ट. प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ

105. प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पाटयों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों की संगत समझों गई सीमा तक जांच की है। कोई भी निवेदन जो केवल पिछले सबमिशन का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

### अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

106. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं:

- क. आयकर छूट के संबंध में सब्सिडी माजन की गणना के संबंध में, निर्यातक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह बेंचमार्क कर दर को 20% के बजाय 10% के रूप में उपयोग करे, जिस पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। अत उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कृपया इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के रूप में 10% को ध्यान में रखते हुए राजसहायता माजन को सही करें।
- ख. भूमि किराया संबंधी सब्सिडी के संबंध में, इच्छुक पार्टी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारी को इस योजना के लिए किसी भी सब्सिडी मार्जिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि निर्यातक बाजार में प्रचलित किराए की तुलना में अधिक किराया दे रहा है।
- ग. इच्छुक पार्टियों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग, संबंधित वस्तुओं का एकमात्र निर्माता होने के नाते, भारत की कुल मांग को पूरा नहीं कर सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता मजबूर हो जाती है। इस एकाधिकार को संरक्षण प्रदान करने से सौर पैनल उत्पादकों के लिये लागत बढ़ेगी, प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम होगी और एकल उत्पाद यानी बोरोसिल रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड को असमान रूप से लाभ पहुँचाकर भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होगी।
- घ. उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि वियतनाम से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास पर शुल्क लगाने से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को नुकसान होगा। चूंकि टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास सौर पैनलों का एक प्रमुख घटक है, इसलिए शुल्क लागत में वृद्धि करेगा, सौर परियोजनाओं को कम किफायती और प्रतिस्पर्द्धी बनाएगा, और भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों को कमज़ोर करेगा। इसलिए, वे दावा करते हैं कि ऐसे कर्तव्य उचित नहीं हैं।
- ङ. यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में पीयूसी के निर्माण और भारत में उसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है और इसलिए, शुल्क बाजार में एकाधिकार पैदा करेगा। शुल्कों से मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ेगा, जिसके कारण भारत में आयात आवश्यक है।
- च. आयात और घरेलू उद्योग के वित्तीय संघर्षों के बीच कोई कारण संबंध नहीं है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि अधिक क्षमता और व्याज लागत के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।
- छ. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बीआरएल ने उपयोगकर्ताओं से गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया है और इसलिए, प्राधिकारी को अंतिम निष्कर्षों में उनका समाधान करना चाहिए।
- ज. इच्छुक पाटयों ने यह भी कहा है कि घरेलू उद्योग हानियां अधीन देशों से आयात के कारण नहीं बल्कि विस्तार से संबंधित वित्तीय बोला, घरेलू उत्पादन में मांग-आपूर्ति अंतर और उच्च मूल्यास एवं व्याज लागतों जैसे अन्य कारकों के कारण हैं।
- झ. एनआईपी की गणना करते समय प्राधिकारी द्वारा नियोजित पूंजी पर उच्च रिटर्न (22%) पर विचार किया गया है और इस बढ़े हुए एनआईपी के कारण, क्षति मार्जिन भी बहुत अधिक है जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च क्षति मार्जिन और शुल्क हैं।

### घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ:

107. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की विस्तृत गणना साझा करने और सत्यापित जानकारी के आधार पर एनआईपी पर विचार करने और सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी का उचित संज्ञान देने और तदनुसार, अंतिम निष्कर्षों में क्षति मार्जिन को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

ख. यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ आयातक, निर्यातिकों की मदद से, एंटी-डंपिंग कर्तव्यों से बचने के लिए "बनावट टेम्पर्ड ग्लास" के बजाय "हीट स्ट्रेंग्ड सोलर ग्लास" नाम से संबंधित वस्तुओं को मंजूरी दे रहे हैं। घरेलू उद्योग का मानना है कि विवरण में इस परिवर्तन का उद्देश्य कर्तव्यों को दरकिनार करना है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि अंतिम निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत हीट सुदृढ़ीकृत सौर ग्लास को भी शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवर्तन विवरण के कारण आयातकों द्वारा कोई अनुचित लाभ न उठाया जाए।

ग. गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के संबंध में, घरेलू उद्योग का दावा है कि इसके उत्पाद आयात के बराबर हैं और गुणवत्ता संबंधी मामूली मुद्रे एक सामान्य व्यावसायिक घटना है। उन्होंने यह भी कहा है कि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों से यह बहुत स्पष्ट है कि क्षति की जांच अवधि अथवा पीओआई के बाद घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कुल गुणवत्ता दावे बहुत कम हैं।

### प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

108. प्राधिकारी ने देखा कि इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अधिकांश सबमिशन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और प्रकटीकरण विवरण में उचित रूप से निपटा गया है। ये, किसी भी अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ के साथ, इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक वर्गों में व्यापक रूप से संबोधित किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की भी जांच की गई है और इन निष्कर्षों के उपयुक्त खंडों के भीतर विधिवत कार्रवाई की गई है।

109. एनआईपी की विस्तृत गणना साझा करने के लिए घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, और सत्यापित जानकारी के आधार पर एनआईपी पर विचार करने के लिए, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य अनुबंध III के साथ पढ़े गए नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है, जैसा कि संशोधित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा विस्तृत गणनाओं को प्रकटीकरण विवरण जारी करते समय घरेलू उद्योग के साथ साझा किया गया है।

110. आयकर छूट योजना के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सत्यापित दस्तावेजों और उपलब्ध डिक्री और वार्षिक लेखा / आयकर रिटर्न कॉपी से कर की दर पर विचार किया है। इसके महेनजर, इस योजना के लिए कर की दर 20% मानते हुए प्राधिकारी द्वारा परिकलित सब्सिडी माजन सही और औचित्यपूर्ण है।

111. भूमि किराया छूट योजना के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण मूल्य निर्धारण तंत्र और अन्य एजेंसियों के साथ इसके समझौते की प्रकृति पर सरकार द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में कोई जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण, प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि संविदागत राशि बाजार दरों पर आधारित है। इसलिए प्राधिकारी ने विचार किया है कि यह कार्यक्रम सब्सिडी नियमों के नियम 7 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पर्याप्त पारिश्रमिक और परिकलित सब्सिडी मार्जिन से कम पर माल या सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है।

112. एकाधिकार के सूजन और मांग और आपूत के अंतर के कारण आयात पर निर्भरता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एकाधिकार का मुद्दा नहीं उठता क्योंकि कई अन्य घरेलू उत्पादक हैं जिन्होंने भारत में विषयगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए विनिर्माण इकाइयां पहले ही स्थापित कर ली हैं। इसके अतिरिक्त, आयातित विषय वस्तुएं भारतीय बाजार में हमेशा बिना सब्सिडी वाले मूल्य पर उपलब्ध होती हैं।

113. प्राधिकारी नोट करता है कि राजसहायता रोधी शुल्क केवल उस गहन जांच-पड़ताल के परिणाम के बाद ही लगाए जाते हैं जिससे यह स्थापित हो जाता है कि राजसहायता प्राप्त आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। इसका उद्देश्य विदेशी निर्यातिकों के अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं का मुकाबला करना और घरेलू उत्पादकों को अनुचित सुरक्षा प्रदान करने के बजाय एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, एंटी-सब्सिडी जांच कई घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति पर विचार करती है, जैसा कि विषय जांच में है, और बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धी गतिशीलता का आकलन करती है। कर्तव्यों को आयात को प्रतिबंधित किए बिना घरेलू उद्योग को नुकसान को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य का आयात उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी विरोधी उपाय समय-समय पर समीक्षा के अधीन हैं, यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो उनकी वापसी की अनुमति मिलती है। इस प्रकार, ये शुल्क

एकाधिकार नहीं बनाते हैं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के प्रावधानों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को बनाए रखते हैं।

114. भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्षों के उपयुक्त पैराग्राफ में पहले ही नोट कर लिया है कि सब्सिडी रोधी शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए इसका भारतीय सौर मिशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान अवसर देश में संपूर्ण मूल्य शृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार पीयूसी के निर्माण के लिए उचित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करेगा।
115. मांग और आपूर्ति के अंतर के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध वर्तमान क्षमता के साथ, यह भारत में मांग का \*\*\*% पूरा कर सकता है। सब्सिडी रोधी शुल्कों की उपस्थिति से आयात बंद नहीं होगा बल्कि यह केवल एक समान अवसर प्रदान करेगा और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
116. घरेलू उद्योग द्वारा निमत अधिक्षमता के प्रभाव और वित्तीय निष्पादन पर इसके प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि मूल्यास और वित्त लागत कुल लागत का \*\*\*% है। इसके मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि ऐसी छोटी प्रतिशतता को घरेलू उद्योग की भारी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
117. गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के संबंध में, प्राधिकारी ने क्षति की जांच अवधि में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और बिक्री रिटर्न के शुद्ध के बदले किए गए मुआवजे का सत्यापन किया है और इसे असंगत पाया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

वर्षवार	कुल बिक्री (रु. लाख में)	गुणवत्ता दावा (रु. लाख में)	बिक्री विवरणी (निवल विक्रय) (1000 रु. लाख में)	कुल दावा (रु. लाख में)	% (कुल दावा/कुल बिक्री)	रेंज (%)
वित्त वर्ष 2020-21	***	***	***	***	***	0-1
वित्त वर्ष 2021-22	***	***	***	***	***	0-1
वित्तीय वर्ष 2022-23	***	***	***	***	***	0-1
पीओआई - CY 2023	***	***	***	***	***	0-1
सीवाई 2024	***	***	***	***	***	0-1

118. प्राधिकारी "बनावट टेम्पर्ड ग्लास" से "गर्मी मजबूत सौर ग्लास" में विवरण परिवर्तन के बारे में घरेलू उद्योग की चिंता को स्वीकार करता है। इस मामले पर विधिवत विचार किया गया है और पाटनरोधी शुल्कों के किसी अपवंचन को रोकने के लिए अंतिम निष्कर्षों में उपयुक्त स्पष्टीकरण शामिल किए गए हैं।

#### ठ. निष्कर्ष

119. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, और इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग के लिए सब्सिडी, क्षति और कारण लिंक के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

क. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% ट्रांसमिशन 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक नहीं है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड। पीयूसी को सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास और हीट स्ट्रेंथ ग्लास जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है।

ख. आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन नियम 6 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभ को ध्यान में रखते हुए, वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन सकारात्मक हैं।

ड. विचाराधीन उत्पाद के आयातों की जांच से पता चलता है कि जांच की अवधि में संबंधित देश से सब्सिडी वाले आयात की मात्रा में कई गुना वृद्धि हुई है। आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन एवं खपत दोनों के संबंध में वृद्धि हुई है।

च. आयात मूल्य घरेलू उद्योग के बिन्नी मूल्य से कम है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य कम कटिंग हो रही है।

छ. आयात मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं रहा है जिसने घरेलू उद्योग को अपने मूल्यों को उचित/वांछित स्तरों तक बढ़ाने से रोका है।

ज. घरेलू उद्योग वित्तीय हानियों, नकद हानियों और नियोजित पूँजी पर नकारात्मक लाभ से प्रभावित है।

झ. प्राधिकारी ने अन्य इच्छुक पाटयों द्वारा किन्हीं अन्य कारकों, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के संबंध में दिए गए प्रस्तुतिकरण की जांच की है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक से क्षति हुई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति संबंधित देश से राजस्वायता प्राप्त आयातों के कारण होती है।

झ. सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। विचाराधीन उत्पाद का आयात उचित मूल्य पर होता रहेगा।

ट. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर राजस्वायता-रोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। यह देखा गया है कि अंतिम अंतिम उपभोक्ताओं पर अनुशंसित उपायों का प्रभाव नगण्य होगा।

#### ड. सिफारिशों

120. यह ध्यान दिया जाता है कि समानांतर एंटी-डंपिंग जांच में प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्ष एफ संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2025 के तहत विचाराधीन उसी उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने 05.11.2024 को प्रारंभिक निष्कर्षों की सिफारिश की थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 26/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से स्वीकार कर लिया था।

121. आगे यह नोट किया गया है कि प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर संदर्भ-मूल्य पर की गई थी और अंतिम निष्कर्षों में भी, प्राधिकारी ने केवल संदर्भ मूल्य के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है। इसलिए, अब एंटी-डंपिंग शुल्क देय है यदि संबंधित वस्तुएं अंतिम निष्कर्ष एफ संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2025 के तहत अधिसूचित संदर्भ मूल्य से नीचे उत्तरेंगी और एडीडी की राशि संबंधित वस्तुओं के उत्तराई मूल्य और उपरोक्त अधिसूचना की शुल्क तालिका के कॉलम 7 में इंगित संदर्भ मूल्य के बीच अंतर की सीमा तक होगी, बशर्ते कि भूमि मूल्य 10 फरवरी, 2025 के संदर्भ मूल्य से कम हो। वह ड्यूटी टेबल।

122. अधिनियम की धारा 9बी(1)(ए) के संदर्भ में, कोई भी वस्तु डंपिंग या निर्यात सब्सिडी की समान स्थिति की भरपाई के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी-डंपिंग ड्यूटी दोनों के अधीन नहीं होगी। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने इस बात का समुचित ध्यान रखा है कि विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी और निर्यात राजस्वायता दोनों के अध्यधीन नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में, यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि पैराग्राफ 50 में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सब्सिडी मार्जिन निर्यात सब्सिडी के अलावा अन्य सब्सिडी से संबंधित है। इसलिए, घरेलू उद्योग को कोई दोहरा संरक्षण नहीं मिलेगा और किसी भी इच्छुक पार्टी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि चूंकि पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी जांच का पीओआई समान है, इसलिए प्राधिकारी ने इस तथ्य का उचित ध्यान रखा है कि पाटन माजन और राजस्वायता माजन के कारण कुल शुल्क पीओआई के लिए परिकलित क्षति माजन के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। वही नीचे दी गई तालिका में भी परिलक्षित होता है:

निर्माता	डंपिंग मार्जिन	डंपिंग मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन	डंपिंग मार्जिन + सब्सिडी मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	सीआईएफ मूल्य
	यूएसडी /एमटी	%	यूएसडी /एमटी	%	यूएसडी /एमटी	यूएसडी /एमटी	%	यूएसडी /एमटी
फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	***	***	***
श्रेणी	-	30-40	-	0-10	-	-	50-60	-
अन्य सभी	***	***	***	***	***	***	***	***
श्रेणी	-	80-90	-	0-10	-	-	50-60	-

123. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि क्षति माजन जो एक ही पीओआई के कारण पाटनरोधी जांच और सब्सिडी-रोधी जांच दोनों के लिए समान है, सह-प्रचालनरत निर्यातिक/उत्पादक अर्थात् फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लि के लिए एक साथ लिए गए डंपिंग माजन और राजसहायता माजन दोनों के योग से अधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि वियतनाम से संबंधित वस्तुओं के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातिकों के लिए पहले ही क्षति माजन के स्तर तक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है और इसलिए कोई अतिरिक्त सब्सिडी रोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

124. निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी, क्षति और कारण संपर्कों की जांच शुरू करने और करने तथा सकारात्मक राजसहायता माजन के साथ-साथ ऐसे राजसहायता आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि राजसहायता और क्षति की क्षतिपूत के लिए निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है कि संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर यहां वण्ट रूप और तरीके से निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए।

125. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच के अधीन अवधि के लिए इन निष्कर्षों में इस प्रकार निर्धारित राजसहायता के माजन और क्षति के माजन के कम के बराबर निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग पर राजसहायता प्राप्त आयातों के हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सके। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, और प्रदान की गई जानकारी और इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, एंटी-सब्सिडी शुल्क के बेंचमार्क/संदर्भ रूप की सिफारिश करना उपर्युक्त समझा जाता है। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए संबंधित देश में उद्भासित अथवा वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के सभी आयातों पर सब्सिडी-रोधी शुल्क के संदर्भ रूप में लगाने की सिफारिश की जाती है। वर्तमान जांच में संदर्भ मूल्य का निर्धारण एंटी डंपिंग जांच में प्राधिकारी द्वारा संस्तुत संदर्भ मूल्य में सब्सिडी माजन अथवा इंजरी माजन में कम जोड़कर किया जाता है। सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के कोल-3 में यथा वण्ट विषय वस्तुओं के अवतरित मूल्य और नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कोल-7 में दर्शाई गई संदर्भ मूल्य राशि के बीच अंतर के रूप में की जाती है, वशर्ते कि अवतरण मूल्य कॉल-7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो। यदि उत्तराई का मूल्य कॉल-7 में दर्शाए गए मूल्य से अधिक है तो सब्सिडी रोधी शुल्क लागू नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए आयातों का उत्तराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित कर निर्धारण योग्य मूल्य और सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं .	शीर्षक/उप-शीर्षक	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कुल धनराशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 र 8541*	टेक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) कोटेड और अनकोटेड ग्लास**	वियतनाम	वियतनाम	फ्लैट (वियतनाम) कं, लिमिटेड	593	एमटी	यूएसडी
2	- वही-	- वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित सभी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित निर्माता के अलावा कोई भी निर्माता	664	एमटी	यूएसडी
3	- वही-	- वही-	वियतनाम के अलावा अन्य सभी देश	वियतनाम	कोई	664	एमटी	यूएसडी

\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

\*\*बनावट वाला कड़ा (टेम्पर्ड) ग्लास जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक न हो और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक हो, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड। उत्पाद को सौर ग्लास, सौर ग्लास कम लोहा, सौर पीवी ग्लास, उच्च संचरण फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड कम लोहे के पैटर्न वाले सौर ग्लास और गर्मी मजबूत ग्लास जैसे विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है।

नोट 1: यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 के लिए, डीजीटीआर द्वारा संबंधित वस्तुओं के लिए अंतिम निष्कर्ष एफ संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2025 के तहत पहले से ही एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई है, इसलिए, उपरोक्त ड्यूटी टेबल के कॉलम 7 के तहत निर्दिष्ट संदर्भ मूल्य के आधार पर एकत्र की जाने वाली शुल्क की राशि एंटी-डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से भुगतान की गई राशि से कम हो जाएगी।

यह स्पष्ट करने के लिए कि एंटी-डंपिंग और एंटी-सब्सिडी ड्यूटी दोनों कैसे काम करेंगे, उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

उदाहरण:

परिदृश्य: जब ADD (कर्तव्य का संदर्भ रूप) और CVD (कर्तव्य का संदर्भ रूप) दोनों लागू होते हैं

क. भाग लेने वाले निर्माता के लिए संदर्भ-आधारित शुल्क 593 यूएसडी / यदि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात का लैंड-वैल्यू 500 यूएसडी /एमटी है, तो डंपिंग रोधी शुल्क 70 यूएसडी /एमटी (570 यूएसडी /एमटी घटाकर 500 डॉलर/एमटी) होगा और काउंटरवेलिंग ड्यूटी 23/एमटी (593-500-70) होगी।

ख. भाग लेने वाले निर्माता के लिए संदर्भ-आधारित शुल्क 593 यूएसडी / यदि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यात का मूल्य 580 यूएसडी /मीट्रिक टन है, तो डंपिंग रोधी शुल्क शून्य/मीट्रिक टन (570 यूएसडी /एमटी घटाकर 5,80 यूएसडी /मीट्रिक टन) होगा और प्रतिकारी शुल्क 13 यूएसडी /एमटी (593-580 डॉलर) होगा।

ग. भाग लेने वाले निर्माता के लिए संदर्भ-आधारित शुल्क 593 यूएसडी / यदि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड द्वारा पीयूसी के लिए भारत को किए गए निर्यात का लैंडेड मूल्य 600 यूएसडी /एमटी है, तो एंटी-डंपिंग शुल्क शून्य/एमटी (570 यूएसडी /एमटी घटाना 600 यूएसडी /एमटी) होगा और काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी शून्य/एमटी (593-600 डॉलर) होगी।

द. आगे की प्रक्रिया

126. इन निष्कर्षों से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

दर्पण जैन, पदनामित प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 11th February, 2025

**Case No. CVD (OI) – 04/2023**

**Subject: Anti-subsidy investigation concerning imports of “Textured Tempered Glass” originating in or exported from Vietnam.**

**F. No. 6/32/2023-DGTR:** - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Anti-Subsidy Rules’ or the ‘Rules’ (hereinafter referred to as “Rules”) thereof.

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Borosil Renewable Limited (“hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the ‘domestic industry’) had filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ‘Authority’), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Subsidy Rules for initiation of an anti-subsidy investigation concerning imports of the Textured Tempered Coated and Uncoated Glass (hereinafter also referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’ or the ‘subject goods’ or ‘TTG’) originating in or exported from Vietnam (hereinafter also referred to as the ‘subject country’).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/32/2023-DGTR dated 13th February 2024, published in the Gazette of India, initiating an anti-subsidy investigation into imports of PUC from the subject country in accordance with Rule 6 of the anti-subsidy rules to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy of the subject goods and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - a. The Authority notified the embassy of Vietnam in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 6 supra.
  - b. The Authority invited the Government of Vietnam for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 26.12.2023, which was attended by the representatives of the Government of Vietnam.
  - c. The Authority issued a public notice dated 13<sup>th</sup> February 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-subsidy investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
  - d. The Authority sent a copy of the initiation notification to the government of the subject country, through their embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users, the domestic industry, the other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.
  - e. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject country, through their embassy in India, in accordance with Rule 7(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.
  - f. The Authority sent an Exporter's Questionnaire to Flat (Vietnam) Company Limited, Vietnam to elicit relevant information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
  - g. The embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
  - h. In response, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire responses:
    - (i) Flat (Vietnam) Co., Ltd
    - (ii) Flat (Hong Kong) Co., Limited
  - i. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(5) of the Rules.
    - (i) Mundra Solar PV Limited
    - (ii) Swelect Energy Systems Limited
    - (iii) Premier Energies Limited
    - (iv) Renewsys India Private Limited
    - (v) Goldi Solar Private Limited
    - (vi) Waaree Energies Limited
    - (vii) Alpex Exports Pvt Ltd
    - (viii) Vikram Solar Pvt Ltd
    - (ix) Topsun Energy Limited
    - (x) Tata Power Solar Systems Limited
    - (xi) Emmvee Photovoltaic Power Pvt Ltd
    - (xii) Navitas Green Solutions Pvt Ltd
    - (xiii) Sova Power Limited
  - j. None of the importers / users / consumers has filed any questionnaire response However, post issuance of provisional findings in the anti-dumping investigation, following users / associations / importers

have made representations in the instant investigation. The Authority has also considered their submissions accordingly.

- i. North Indian Module Manufacturer Association (“NIMMA”)
- ii. Sustainable Projects Developers Association (SPDA)
- iii. Goldi Solar Pvt. Ltd.

k. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

l. Request was made to the DGCI&S to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

m. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-subsidy duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

n. Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry and exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Findings.

o. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> January 2023 to 31st December 2023 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covers a period of 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

p. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in the present final findings.

q. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

r. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

s. The Authority provided time for providing comments on PUC/PCN. However, none of the interested parties provided any comment on the same.

t. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority has examined the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which has formed the basis for conclusions for the present final findings.

u. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 29.01.2025. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 05.02.2025.

v. The Authority has examined all post – disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

- w. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation
- x. '\*\*\*\*' in this notification represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 83.52.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The Authority, at the stage of the initiation notification, defined the product under consideration as follows:

*"3. The product under consideration for the present investigation is 'Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated'.*

#### C.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

5. None of the interested parties have provided any comments on the PUC.

#### C.2 Submissions made by the domestic industry.

6. The domestic industry made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and the like article:

- a. The product under consideration is 'Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated' originating in or exported from Vietnam
- b. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Solar Glass Low Iron, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass, heat strengthen glass, etc. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.
- c. The subject products are predominantly imported under tariff classification at the 8-digit level is 70071900 even though the same are being classified and imported under various subheadings of the Customs Tariff Act, 1975, as can be seen from the import data. However, it is noted that subject goods are also being imported in the sub-headings 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011 as evidenced by the import data. Moreover, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.
- d. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The applicants have claimed that the subject goods, which are coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

#### C.3 Examination by the Authority.

7. The product under consideration in the present investigation was, at the stage of initiation, defined as 'Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated.

8. The PUC is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass, heat strengthen glass, etc. The PUC is used as a component in solar photovoltaic panels and solar thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.

9. The product under consideration is classified under the category 'Glass and Glassware' in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

10. The Authority notes that there is no known difference in product under consideration produced by the Indian industry and exported from the subject country. Product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country in accordance with the anti-subsidy Rules.

#### **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.**

11. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of domestic industry and standing

##### **D.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.**

12. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

- The present application has been filed by Borosil Renewables Limited (BRL) and they are the major producers of the subject goods in India.
- There are five (5) other known producers of the subject goods in India.
- The domestic industry has not imported the subject goods from the subject country and is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India.

##### **D.3 Examination by the Authority**

13. Rule 2(b) of the Anti-Subsidy Rules defines the domestic industry as under:

'(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the *like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*'.

14. The Authority notes that the application has been filed by Borosil Renewables Limited (BRL). It is further noted that apart from applicant industry, there are 4 other producers namely Govind Glass & Industries Ltd, Triveni Renewables Private Ltd., Vishakha Glass Pvt. Ltd., and Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd. who have commenced production in the POI.

15. The Authority further notes that the applicant has not imported the subject goods from the subject country and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Further, the production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. Thus, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Subsidy Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 6(3) of the Anti-Subsidy Rules.

#### **E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS ISSUES**

##### **E.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.**

16. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

- That the trade remedial measures on imports of textured tempered glass have been in place for over a decade. This prolonged reliance undermines the incentive for the domestic industry to improve efficiency and adapt to market changes, fostering dependency instead of competitiveness. It is further submitted that even WTO principles discourage the indefinite extension of trade remedies. Such prolonged measures distort market dynamics and reduce innovation, while unfairly impacting downstream industries dependent on imports.
- It was also submitted that the Domestic industry in previous investigations conducted in 2017, 2021, and 2023 consistently failed to prove that imports caused material injury to the domestic industry.

- c. Interested parties have requested imposing duties for 3 years instead of 5 as this would strike a balance between protecting the domestic industry and encouraging competitiveness. This will align with WTO principles discouraging prolonged protectionism.
- d. The responses of the association cannot be rejected. They also submitted that their submissions need to be addressed properly by the Authority.

### **E.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.**

17. The submissions of the domestic industry with regard to the miscellaneous submissions are as follows:

- a. In relation to submission / participation by user association, Domestic Industry submitted that as a matter of conscious and strategic decision, user associations never provide the requested information or files information required under the law / trade notice issued by the Authority. Since they are also being represented by legal professional, it would be injustice with the other interested parties including Domestic Industry to accept their response or even allow them to make further submissions in the investigation. Even post hearing also, none of the user associations have fulfilled their legal obligations. Therefore, the Authority should carefully consider their unsubstantiated submissions.
- b. In relation to the issue of history of cases, Domestic Industry submitted that the history of the previous cases, that too, against different sources altogether, is of no legal or factual relevance to the fact of this case. The Authority is required only to see whether a case for imposition of anti-subsidy duties / extension of anti-dumping / subsidy duties is made out in the facts and circumstances of the case. It is further submitted that the previous measures are of no consequence in the present case, if the exporters are getting subsidy, then the domestic industry has no other option but to seek remedy under the laws of the land for appropriate relief. Since the exporters has not dispute receipt of benefit, Domestic Industry has all the rights to seek protection against such practices.
- c. In relation to submission of interested parties that in the previous investigations, the Authority has not found any injury, Domestic Industry submitted that at a mere glance of the previous investigations against China and Malaysia, it would be clear to interested parties that the Authority has found injury in all the cases. However, against Malaysia, the Authority did not find any dumping and therefore, no duties were imposed against it.
- d. Regarding impairment of rights of interested parties to participate, the Domestic Industry has submitted that once the initiation notification is published in the Official Gazette, it is presumed that all the interested parties have been sufficiently informed.
- e. In relation to request of imposing duties for 3 years instead of 5, the Domestic Industry has submitted the interested parties failed to provide a single reason in support of their claim of recommending duties for 3 years and therefore, the Authority should disregard any such unsubstantiated and irrational submissions of the interested parties.

### **E.3 Examination by the Authority**

18. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-subsidy Rules provides as follows:

Confidential information:

- (1) *Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule(2) of rule 14, sub-rule(4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as ,such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.'*

19. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard

to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

20. It has been contended that the anti-dumping /subsidy duty has been in force for more than a decade. In this regard, the Authority notes subject investigation is a fresh proceeding and does not involve a continuation of previously imposed duties. The Authority has conducted this investigation in strict compliance with the provisions of the Anti-Subsidy Rules. The Authority further notes that the Domestic Industry is fully entitled to legal recourse and protection, if it is established that exporters from any country are engaged in unfair trade practice that is causing injury to the Domestic Industry.

## **F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGINS**

### **F.1 Submissions made on behalf of other interested parties.**

21. The other interested parties have made the following submissions with regard to subsidy schemes and margins.

- The Authority has initiated an investigation without analyzing the programs adequately. The applicant did not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, namely, (a) financial contribution, (b) benefit, and (c) specificity.
- Most of the subsidies alleged by the applicant are simple assertions without any actual evidence.
- The Authority should use the verified data filed by the exporter for analyzing the subsidy schemes and margins for any purpose.

### **F.2 Submissions made by the domestic industry**

22. The domestic industry has made the following submissions with regard to the subsidy and subsidy margin:

- There is sufficient evidence showing that exporters/ producers/ their affiliates of the subject goods in the subject country have benefited from various countervailable subsidy programs.
- The average useful life for machinery used in subject product in Vietnam is 5 to 7 years. The import duty exemptions on inputs for exported products are not countervailable as long as the exemption is extended to the production of exported products only. The Government of Vietnam must have a system in place to confirm the inputs consumed for exported products. If such a system does not exist or is not applied effectively, it will lead to countervailing of the entire amount of the exemption.
- Government of subject country has not filed a response/ nor provided any meaningful information. Only the government can provide detailed information related to whether the said scheme is countervailable or not. The responding exporter can only provide information whether any benefit was received or not. In other jurisdictions, where the Government of the exporting country does not cooperate, the investigating authorities rely on the facts available and determine the countervailability of the schemes.
- As per the information available in public domain, there are certain benefits available to the exporters of the subject goods in Vietnam. The government of Vietnam has also extended certain benefits to participating exporter also. Domestic Industry humbly request the Authority to calculate benefits for all the schemes irrespective of whether the same are identified by them or not in its application.

### **F.3 Calculation Methodology**

23. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lay down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

**F.3.1 Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners**

- i. **Program 1 & 2 (Import duty exemption on imports of raw materials for enterprises in non-tariff zones; Import duty exemption on imports of machinery and equipment)**
  - a. **Submission by the Domestic Industry**

24. Vietnam's import duty exemption program (Import duty exemption on imports of raw materials for enterprises in non-tariff zones) provides tax relief for manufacturers in non-tariff zones specifically targeting export-oriented enterprises in zones like export processing and special economic zones. The program allows duty-free import of raw materials for producing export goods like textured tempered glass. Under import duty exemption on imports of machinery and equipment program it has been submitted that companies can import duty-free capital assets including machinery, equipment, components, parts, raw materials, specialized vehicles, and specific building materials.

25. The non-recurring, region-specific benefit aims to support industrial development by forgoing government revenue for manufacturers importing raw materials as well as capital assets in targeted regions.
  - b. **Submission by Government of Vietnam/other interested parties**

26. Government of Vietnam (GOV) has submitted that import and export duties are governed by the Law on Import and Export Duties. GOV has issued Decrees and Circulars including Law No. 107/2016/QH13 and other relevant guidance for implementation of this scheme. This is an incentive policy for export processing enterprises. In cases where imported raw material is used for manufacturing of goods meant for exports, the inputs will be exempt from import duty. It has further been submitted that there is no change in this scheme and it was operational during period of investigation. Law No. 107/2016/QH13 also provides for incentives on importation of fixed assets.

27. The participating exporter in its response has claimed to have received benefit under this scheme.
  - c. **Examination by Authority**

28. The Ministry of Finance (MOF) and the General Department of Vietnam Customs (GDVC) under MOF administer the import and export duty scheme. Governed by the Law on Import and Export Duties 107/2016/QH13 and supported by various decrees and circulars, this system provides guidelines on customs procedures, duty exemptions, and tax administration. Exemptions apply to raw materials, supplies, and components used in the production of exported goods, with businesses required to report the quantity and value of imported materials. The program provides for exemption on import duty on raw materials used in the manufacture of exported product. The Authority notes that no evidence and details have been furnished regarding the tracking system maintained by GDVC to ensure that entire raw material imported duty free is consumed in the production of exported product.

29. The Authority further notes that Law No. 107/2016/QH13 also provides for the following:

*“11. Imports as fixed assets of an entity eligible for investment incentives as prescribed by regulations of law on investment, including:*

    - a) *Machinery and equipment; components, parts, spare parts for assembly or operation of machinery and equipment; raw materials for manufacture of machinery and equipment, components, parts, or spare parts of machinery and equipment;*
    - b) *Special-use vehicles in a technological line directly used for a manufacture project;*
    - c) *Building materials that cannot be domestically produced.*

*Exemption of import duty on the imports specified in this Clause also applies to new investment projects and extension projects.”*

30. In view of the above, the Authority notes that the program 'Import duty exemption on imports of raw materials for enterprises in non-tariff zones' provide for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, the Authority holds that the countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

31. In relation to 'Import duty exemption on imports of machinery and equipment', it is noted that Law No. 107/2016/QH13 also provides for duty exemption of fixed assets for new investment projects and extension projects. Thus, this scheme provides financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is only available to companies that meet specific eligibility criteria as noted above. Therefore, the Authority holds that the countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

**ii. Program No. 3: Reduction of corporate income tax:**

**a. Submission by the Domestic Industry**

32. The agency responsible for administering this program is Hai Phong City Tax Department, Vietnam. This program offers corporate tax exemptions and reductions for companies for making new investments. As per the scheme the companies meeting eligibility criteria are exempt from 100% corporate income tax for 4 years and 50% reduction in tax payable for the following 9 years. This applies to all activities conducted by the company, and no specific requirements exist regarding export performance, use of domestic goods, or specific industries. The key condition is that the company must operate in regions designated by the Government of Vietnam, making this scheme specific to certain geographical regions.

33. The Domestic industry has requested the Authority to countervail the subsidy as the exporter has also admitted to have availed the benefit under this scheme.

**b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties**

34. It is submitted that the program offers corporate tax exemptions and reductions for companies investing in socialization projects in difficult socio-economic conditions, as defined by the government. Specifically, companies meeting eligibility criteria are exempt from corporate income tax for 4 years and benefit from a 50% reduction in tax payable for the following 9 years. This applies to all activities conducted by the company, and no specific requirements exist regarding export performance, use of domestic goods, or specific industries. The key condition is that the company must operate in regions designated as having difficult socio-economic conditions.

35. The quantum of assistance is based on the criteria outlined in the Law on Corporate Income Tax. Companies participating in the program must maintain records, such as tax returns, to document the benefits received. The program provides benefit, exempting companies from 100% corporate income tax for 4 years and offering a 50% tax reduction for the subsequent 9 years. This program is still in operation. The exporter has accepted to have received benefit under this scheme.

**c. Examination by Authority**

36. Authority notes that the program provides exemption from income tax is governed by Corporate Income Tax 14/2008/QH12 (amended by Law 32/2013/QH13 and Law 71/2014/QH13) and Law of Foreign Investment as amended in 2000. The companies that meet the eligibility requirements are granted a complete exemption from Corporate Income Tax (CIT) for 4 years, followed by a 50% reduction in payable tax for the next 9 years. Thus, the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also sector specific and region specific because it is limited to encouraged sectors or encouraged geographical regions. The exporter has accepted to have received the benefit under this scheme. The Authority, therefore, holds that countervailing duty should be imposed against this program.

**iii. Program No. 4: Exemption and reduction of land & water rent**

**a. Submission by the Domestic Industry**

37. The Ministry of Finance in Vietnam provides guidelines for implementing the law No. 67/2014/QH13, while local tax authorities handle land rent dossiers. During the POI, land and water surface rent collection was governed by Decrees 46/2014/ND-CP, which offer rent exemptions and reductions for projects in disadvantaged areas or with significant investments. Under this program, the regional and local authorities provide land to the manufacturers of the subject goods in Vietnam. It is further submitted by the Domestic Industry that since the land was provided at pre-fixed rate, the purchase price or landed value may not reflect the correct picture.

**b) Submission by Government of Vietnam/other interested parties**

38. It is submitted by the GOV that in order to encourage enterprises to invest into geographical regions or areas with especially difficult socio-economic conditions, the GOV pursues a policy of exemption and reduction of land rent for companies who have investment projects in such regions. It is further submitted that the entities entitled to the exemption and reduction in the land rent and water surface rent are prescribed in Article 19 and Article 20 of the relevant Decree. Under this scheme, the tax authorities shall determine the amounts payable by the land renters or water surface renters and the amount that is exempted or reduced, in particular. The Directors of the Provincial Departments of Taxation shall decide the exempted amounts with regard to the economic organizations, foreign organizations and individuals. The Ministry of Finance shall give instructions on the procedures for the exemption and reduction in the land rents and water surface rents. This clause is regulated by Article 15 Circular No. 77/2014/TT-BTC regarding procedures for exemption and reduction of land rents, water surface rents. The application submitted to the

tax authority shall be processed according to regulations of law on procedures for reception and transfer of documents on determination of financial obligations of the land user. According to the application mentioned in Clause 3 of this Article, the tax authority shall determine and decide the remitted land rent or water surface rent. It is also submitted that this program is still operational.

39. The exporter, however, has submitted that they have not received any benefit under this scheme as the rent applied to different companies is non-comparable for the rent applied to each company shall be determined case by case by the Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company. The Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company would set the minimum acceptable benchmark. The exporter however, submitted that the said minimum acceptable benchmark cannot be disclosed because it is the confidential information of the Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company and also used to negotiate with other companies. The exporter submitted that despite Haiphong People's Government holds 25.1 % equity of Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company, Haiphong People's Government does not engage in the said company's daily operations. Therefore, the exporter submitted that the rent applied to them is completely based on the market price and therefore, this scheme should not be seen as subsidy from any perspective

**b. Examination by Authority**

40. The Authority notes from the response filed by GOV that under this scheme, the tax authorities shall determine the amounts payable by the land renters or water surface renters and the amount that is exempted or reduced, in particular. The Directors of the Provincial Departments of Taxation shall decide the exempted amounts with regard to the economic organizations, foreign organizations and individuals. Further, the GOV has neither denied nor accepted the receipt of any benefit by producers / exporters of the subject goods under this scheme. GOV has advised to gather this information from the participating producer. It is further noted that there is a significant degree of government oversight and direction in the context of the Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone through HEZA, which manages Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone (DEEPC). The GOV approves and grant investment incentives, including land-related incentives like rental exemptions or reductions through various ministries and agencies (including HEZA). It is also noted that GOV through various ministries and agencies (including HEZA), is responsible for approving and granting investment incentives, including land-related incentives like rental exemptions or reductions. It is thus noted that the Government of Vietnam (GOV) continues to exercise authority over land-use pricing, including determining lease rates for land leased directly from the government. Additionally, restrictions remain on land subleased by private parties, as the land-use contracts held by these private entities are granted by government agencies established under specific government decrees. Hence, the Authority notes that the acquisition of land-use rights in Vietnam is not governed by market-driven principles.

41. While the participating exporter has presented contracts with the local authorities and shown payments according to such contracts and has contended that the decided rates are market driven, the Authority in the absence of submission of any information by GOV in its questionnaire response on the complete price fixation mechanism and the nature of its agreement with the Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company cannot conclude that the contracted amount is based on the market rates.

42. In view of the aforesaid, the Authority notes that this program provides financial contribution in the form of provision of goods or services at less than adequate remuneration. The program is also specific because it is region specific and is limited to certain encouraged sectors. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program. It is further submitted that in the absence of any verifiable information, the Authority has resorted to the facts available in terms of Rule 7(8) for this scheme.

iv. **Program No. 5: Investment Support**

**a. Submission by the Domestic Industry**

43. The Ministry of Planning and Investment in Vietnam administers investment incentives under the Law on Investment 61/2020/QH14. This scheme is applicable to both foreign and domestic investors. Eligible projects include those in specific sectors, meeting financial or employment thresholds. Incentives are available for new and expansion projects, excluding those in mineral mining, commercial housing, and certain excise-taxed goods.

**b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties**

44. It is submitted that under the Law no. 67/2014/QH13, the Vietnamese government provides non-recurring financial support to those companies which are situated in disadvantaged industrial parks through two mechanisms: partial capital investment support and concessional loan capital. The program offers grants via direct fund transfers or concessional loans to enhance technical and social infrastructure, specifically targeting companies located in economically challenged geographic zones. Investment incentives shall be given to new investment projects and expansion projects. The level of each type of incentives shall be

specified by regulations of the Law on Taxation, the Law on Accounting and the Law on Land. These benefits will not apply to Projects on investment in mineral mining, Projects on investment in manufacturing/sale of goods/services subject to special excise tax according to the Law on Special Excise Tax, except for projects on manufacturing of automobiles, aircrafts and yachts.

**c. Examination by Authority**

45. It is noted from the response of the GOV, that during the POI, investment incentives and assistance are provided under the Law on Investment 61/2020/QH14. Under the Law 61/2020/QH14, all entities can be eligible for the investment incentives and assistance regardless of whether they are invested by a foreign investor or a domestic investor. During the period of investigation, the criteria for determining eligibility for investment incentives or assistance are laid down in Law 61/2020/QH14 (Article 15). It is further noted that the GOV has not expressly confirmed that this scheme is not applicable to the producers/ exporters of the subject goods. The Authority further notes that as per the verified data on record, the cooperating exporter has not availed any benefit under this scheme.

46. In view thereof, the Authority notes that GOV is providing financial benefits to companies located in economically challenged geographic zones. Investment incentives shall be given to new investment projects and expansion projects. Thus, this scheme provides financial contribution in the form of grants and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is only available to companies that meet specific eligibility criteria as noted above. Therefore, the Authority holds that the countervailing duty should be imposed against this subsidy program. However, as per the verified data on record, the cooperating exporter has not availed any benefit under this scheme. The margins for all non-cooperating exporters have been determined based on the facts available in terms of Rule 7(8).

**v. Program No. 6: Investment Credit by Vietnam Development Bank**

**a. Submission by the Domestic Industry**

47. The Ministry of Planning and Investment in Vietnam administers investment incentives under the Law on Investment 61/2020/QH14. These incentives apply to both foreign and domestic investors. Eligible projects include those in specific sectors, meeting financial or employment thresholds (e.g., at least VND 6,000 billion in capital, VND 10,000 billion in annual revenue, or 3,000+ employees). Incentives are available for new and expansion projects, excluding those in mineral mining, commercial housing, and certain excise-taxed goods. Eligibility is based on project compliance, not export performance or the use of domestic over imported goods.

**b. Submission by Government of Vietnam/other interested parties**

48. It is submitted that Decree 32/2017/ND-CP on state investment credit prescribes the policy on state investment credit to be implemented by the Vietnam Development Bank (VDB). VDB is a policy bank which is 100% owned by the state and aimed at performing the state policy lending. The lending functions of VDB includes implementing policies on investment credit for development (granting loans for development investment; post-investment support; investment credit guarantee); implementing policies on export credit (granting loans for export; export investment guarantee; guarantee for bidding participation and for implementation of export contracts). Since May 15, 2017, with the issuance of Decree 32/2017/ND-CP, VDB has no longer provided export credits. As per the submissions of the GOV, VDB only provided state investment credits to subjects under Appendix on Lists of projects eligible to borrow investment loans attached with in and in accordance with Decree 32/2017/ND-CP during the POI. The GOV has further submitted that textured tempered coated and uncoated glasses do not fall within the said lists.

**c. Examination by Authority**

49. The Authority notes that Decree No. 32/2017/ND-CP, issued by the Government of Vietnam on March 31, 2017, outlines the policy on state investment credit. The decree includes an appendix which mentions an extensive list of projects eligible for investment loans. The Authority notes that Vietnam Development Bank is providing financial benefits to list of projects defined under Appendix to the above Decree, as amended from time to time. Thus, this scheme provides financial contribution in the form of grants and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is only available to projects that appear in the list. However, the Authority further notes that the subject goods do not figure in the said appendix and therefore, are not eligible for financial grants by VDB. Therefore, the Authority holds that the countervailing duty should not be imposed against this subsidy program.

**F.3.8 Subsidy margin.**

50. The subsidy margin determined in the present investigation are as follows:

Program No.	Name of Program	Flat Glass Vietnam	Range %	Nature of Subsidy
Program No. 1	Import Duty Exemption on Raw material	***%	0-5	Export Contingent Subsidy
Program No. 2	Import Duty Exemption on Procurement of Fixed Assets	***%	0-5	Domestic
Program No. 3	Income Tax Exemption	***%	0-10	Domestic
Program No. 4	Exemption and reduction of land & water rent	***%	0-5	Domestic
Program No. 5	Investment Support	-	-	Domestic
Program No. 6	Investment Credit by Vietnam Development Bank	-	-	Domestic
	<b>Total</b>	<b>***%</b>	<b>0-10</b>	Domestic
	<b>Net Countervailing Duty for Flat (Vietnam) Co., Ltd.</b>	<b>***%</b>	<b>0-10</b>	Net of Export contingent Subsidy
	<b>Residual</b>	<b>***%</b>	<b>0-10</b>	

## G. INJURY AND CAUSAL LINK

### G.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

51. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link.

- Domestic production volumes rose consistently during the period under investigation, disproving claims that imports suppressed production. This growth indicates that the domestic industry managed to increase output despite alleged injury from imports, suggesting that imports did not impede their competitiveness.
- While import volumes increased, the domestic industry's selling prices also rose during some periods, indicating that imports did not lead to price suppression. The injury claimed by the domestic industry is not aligned with this data and points to other underlying factors.
- The injury attributed to imports is overstated because it fails to consider significant external factors, such as raw material price volatility, global inflation, and supply chain disruptions. These factors independently impacted the domestic industry's financial health.
- The domestic industry's losses stem from decisions like capacity over-expansion, which strained their financial resources. This expansion resulted in higher depreciation and interest costs, compounding operational inefficiencies. These self-inflicted issues cannot be attributed to imports.
- The 22% Return on Capital Employed (ROCE) used to calculate NIP is excessive compared to renewable energy industry standards, which are typically around 14-15%. Such inflated benchmarks exaggerate injury margins, leading to unfair conclusions about injury from imports. The lack of clarity and consistency in the methodology used for calculating NIP has raised concerns among stakeholders. A standardized approach would enhance fairness and ensure that duty recommendations are based on realistic and equitable assessments.
- The evidence fails to establish that imports are the primary cause of injury. Market dynamics, such as fluctuating demand and rising input costs, were likely more influential in determining the domestic industry's financial outcomes.
- The domestic industry's outdated production technology and inefficient operations are key contributors to its challenges. Without modernizing their processes, the industry's financial problems will persist, irrespective of the presence of imports.
- Imported solar glass adheres to internationally accepted standards, including those established by leading certification bodies like IEC (International Electrotechnical Commission). Domestic producers

have yet to fully align their products with these benchmarks, particularly in terms of durability, optical clarity, and anti-reflective coating efficacy.

- i. Renewable energy project developers argue that using lower-quality domestic glass can lead to higher maintenance costs and efficiency losses over time, discouraging foreign investment in India's solar sector. This reliance on imports is not a matter of preference but of necessity to ensure long-term project viability and performance.
- j. Imported textured tempered glass offers innovative features, such as bifacial technology compatibility and high thermal stability, which domestic manufacturers have not yet been able to replicate. This technological gap further reinforces the reliance on imports for modules intended for large-scale solar projects.
- k. The domestic industry's failure to invest in R&D to meet these specialized needs exacerbates the issue, leaving downstream industries no choice but to source high-quality glass internationally.
- l. Quality issues in domestically produced glass can compromise module efficiency, increase energy losses, and reduce the overall lifespan of photovoltaic systems, making imports indispensable for ensuring reliability and competitiveness in international markets.
- m. It was also emphasized that quality variations in local glass have previously resulted in increased rejection rates during module manufacturing, driving up operational costs for manufacturers and forcing reliance on imports to maintain production schedules and quality benchmarks.
- n. Interested parties have highlighted significant concerns regarding the inability of domestic producers to meet the strict specifications required by global standards for advanced solar modules. For instance, imported glass often achieves transmission rates exceeding 91%, while domestic producers struggle to consistently meet these thresholds, leading to performance issues in solar panels.

## G.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

52. The domestic industry has submitted as follows on the issue of injury and causal link:

- a. Despite the presence of the domestic industry and other producers, the imports have dominated the entire market. The imports from subject country constitute remained significant of the market share during the period of investigation.
- b. The subsidized imports are undercutting the prices of the domestic industry which is significantly positive during the period of investigation.
- c. The subject imports have continuously caused strain on the prices of the domestic industry as they were priced lower than the selling price of the domestic industry throughout the injury period.
- d. In the period of investigation, the landed value of the subject goods was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. This clearly shows the price pressure on the domestic industry.
- e. The subsidized imports have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry.
- f. The share of the domestic industry in the demand is a meagre \*\*\*%, despite having sufficient capacity to meet the Indian demand.
- g. Due to the constant pressure of subsidized imports, the domestic industry has not been able to dispose of its production sufficiently. As a result, the domestic industry was forced to undertake exports to dispose of their inventories to avoid piling up the goods.
- h. In the period of investigation, the profitability of the domestic industry has declined by nearly \*\*\*% when compared to the base year. The domestic industry has also faced significant cash losses and a negative return of \*\*\*%. This is substantial by any standards.
- i. The domestic industry has also submitted that post initiation, their losses increased substantially and imports also increased.
- j. There is a critical need for the imposition of an interim duty in the present case because the domestic industry has been struggling to maintain its operations, leaving aside reaching desired levels.
- k. In relation to the alleged high return, it is submitted that the return of 22% has been the consistent practice of the DGTR which has also been upheld by the higher authorities in a number of cases. Moreover, the return of 22% is on capital employed (working capital and fixed assets) determined with proper guidelines and is used for the limited purpose of arriving at the NIP. Domestic Industry also highlighted that 22% of ROCE typically translated to \*\*\* to \*\*\*% profit on cost and even less in many cases and, therefore, this cannot be considered as high or extraordinary. In support of 22%,

Domestic Industry has also provided judgements wherein courts / tribunals have upheld 22% return on capital employed.

1. The Domestic Industry emphasizes that injury parameters cannot be analyzed in isolation. Domestic Industry has submitted that both price undercutting and price depression exist in the present case and therefore, requirements of Article 3.2 of the AD Agreement are clearly met with. Similarly, as per Article 3.4 of the AD Agreement, the Domestic Industry highlights that all relevant economic factors must be evaluated collectively, even if not all of them may indicate injury.
- m. Domestic Industry also provided statistical evidence of injury and submitted that increased installed capacity to meet increasing demand, should not be interpreted as an absence of injury, as claimed by the interested parties. They have also highlighted that there is huge increase in the inventories despite higher production, sales and demand, indicating injurious impact of subject goods from Vietnam.
- n. It is further submitted that verified data on record shows that Domestic Industry is suffering critically as there are losses, negative return on investment, coupled with increased inventories and reduced capacity utilization declining sales realization and losses, worsening financial performance, and reduced market share.
- o. In relation to demand and supply gap, the Domestic Industry submitted that Indian producers can meet \*\*\*% of Indian demand but has faced challenges due to dumped imports since the discontinuation of anti-dumping duties in 2022. It is further submitted that despite added module manufacturing capacities, domestic glass production has not gone up essentially due to unremunerative prices on account of incessant dumping / subsidy.
- p. Domestic Industry has submitted that levy of provisional duties has revitalized plans for capacity expansion. It is also stated that even the 2024 budget speech of the Hon'ble Finance Minister supports these efforts. It is further submitted that due to sufficient domestic solar glass capacities existing in the country, exemptions of basic customs duty on imports of the subject goods have been discontinued.
- q. In relation to quality claims, Domestic Industry submitted that the quality of its goods is on par with imported goods. It is further submitted that the claims of inferior quality by some parties lack factual evidence, as no supporting data or impact on final products has been provided. In relation to specific issues raised by the interested parties, the Domestic Industry has submitted that most of the issues raised by the interested parties barring some stray instances, are not concerned with the product as such. It has been further submitted that transition from "glass-to-back sheet" to "glass-to-glass", technology has increased demand and is unrelated to quality concerns. Further, issues relating to pasting, blasting during lamination, adhesive failure cannot be attributed to quality of glass. None of the interested parties has provided any evidence to show that their modules were downgraded in quality index by their users because of using subject goods produced by Domestic Industry.
- r. In addition to above, it is submitted that the quality claims against the Domestic Industry account for less than \*\*\*% of total sales volume, indicating its insignificance. Domestic Industry further submitted that the Authority has consistently dismissed quality-related arguments when domestic and imported products are substitutable in the market.
- s. In relation to claims of higher depreciation and interest costs, Domestic Industry submits that both depreciation and interest costs account for only \*\*\*% of total costs, which is insufficient to account for the massive losses and cash losses of the industry.

### **G.3 Examination by the Authority**

53. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.
54. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provides as follows:
  13. Determination of injury-
    - (1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.
    - (2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –

- there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and
- the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

55. In relation to issues related to appropriate return for the purpose of Non-Injurious Price, it is noted that the Authority has consistently used 22% return on capital employed in all its investigations and no substantive grounds have been made to deviate from Authority's consistent practice which has been also upheld by Courts/Tribunals in the past.

56. In relation to quality issues, it is noted that none of the interested parties has provided any concrete evidence related to technical difficulty in achieving specific quality specifications by the Domestic Industry. Some interested parties have submitted email communications and minutes of the meeting stating quality issues pertaining to the goods produced by the Domestic Industry. Domestic Industry has refuted the claims supported by email communications and minutes of the meeting with customers. The Authority also checked the compensation given by the Domestic Industry for not meeting the quality during the POI and it was found to be minuscule. It is also noted that total quality claims received by the Domestic Industry is less than \*\*\* % of their total sales.

57. It is noted that the Authority has carried out a parallel investigation with regard to injurious dumping from both China and Vietnam wherein the period of investigation was identical to the period considered in the present investigation i.e., January 2023 to December 2023. The Authority further notes that in the said findings a positive determination is made with regards to the injurious imports from China as well as Vietnam. The determination made therein is relevant here as well.

58. The Authority has examined the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

### Volume effect of the subsidized imports

#### G.3.1 Assessment of demand / apparent consumption

59. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from Subject Country	MT	656	78,093	1,03,277	1,19,285
Imports from Other Countries	MT	1,58,144	1,20,343	2,92,247	6,76,269
Total Imports	MT	1,58,799	1,98,436	3,95,524	7,95,555
<b>% Share of Imports in Total Imports</b>					
Imports from Subject country	%	0.41%	39.35%	26.11%	14.99%
Imports from Other Countries	%	99.59%	60.65%	73.89%	85.01%
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	107	188
Sales of the Other Producers	MT	-	-	-	***
Trend	Indexed				100
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	203	411
Share in Demand					
Imports from Subject Country	Indexed	***	***	***	***

Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Trend	Indexed	100	9,950	7,766	4,429
Imports from Other Countries		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	91	104
Total Imports		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	123	122
Domestic Sales		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	53	46
Sales of the Other Producers		0	0	0	***
Trend	Indexed				100
Production-PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	129	209
<b>Import from Subject countries in relation to</b>					
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	9,944	7,761	4,427
Production-PUC	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	10,060	12,193	8,716

60. In view of the observations made in Para 40, the Authority notes the following with respect to volume related parameters:

- Imports from countries (China and Vietnam) showed a significant increase over the years. Starting at 29,980 MT in 2020-21, they surged to 779,017 MT during the POI (Period of investigation).
- Vietnam's Contribution: Imports from Vietnam increased from 656 MT in 2020-21 to 119,285 MT in the POI, with the highest spike between 2020-21 and 2021-22.
- Total Imports: Reflecting the rise in imports from subject country, the total imports grew significantly from 158,799 MT in 2020-21 to 795,555 MT in the POI, indicating a shift towards imports from China and Vietnam.
- Sales of the domestic industry: Sales volumes of the domestic industry remained relatively stable over the first three years, ranging between \*\*\* MT to \*\*\* MT, and increased to \*\*\* MT during the POI.

- e. Sales of Other Domestic Producers: There were no sales recorded for other domestic producers from 2020-21 to 2022-23. Sales of \*\*\* MT were made during the POI.
- f. Total Demand/Consumption: The overall market demand or consumption has been on an upward trend throughout the period, growing from \*\*\* MT in 2020-21 to \*\*\* MT during the POI, indicating increased market activity.
- g. Imports in relation to consumption and production has increased manifold during the injury investigation period.

### G.3.3 Price effect of subsidized imports

61. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the subsidized imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

#### a) Price undercutting

62. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. It is seen that the price undercutting is positive during the period of investigation.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Landed value	Rs./MT	65,191	50,435	44,181	40,265
Trend	Indexed	100	77	68	62
Domestic selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	113	95
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	39	61	33
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
Price Undercutting %	Range	Negative	10-20	20-30	10-20

It is noted that during the period of investigation, the subject imports were undercutting the prices of the domestic industry.

#### b) Price suppression/depression

63. In order to determine whether the subsidized imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales Domestic	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	119	105
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	111	93
Landed Price	₹/MT	65,191	50,435	44,181	40,265
Trend	Indexed	100	77	68	62

64. The Authority notes from the above that the landed value of the imports was below the selling price of the domestic industry throughout the injury period.

65. During the period of investigation, the landed value of the subject goods remained lower than the cost of sales of the domestic industry and its domestic selling prices. This prevented the domestic industry from

keeping its price in tandem with the cost of sales. It is, therefore, noted that the imports have prevented price increase, which otherwise, would have occurred. Thus, the imports have had suppressing effect on the prices of the domestic industry.

#### **G.3.4 Economic parameters related to the domestic industry**

66. Anti-Subsidy Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of subsidized imports on domestic producers of the subject goods. The Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of subsidy; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

##### **i) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes**

67. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	128	232
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	120	203	411
Total Production (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	115	125	199
Production PUC only (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	118	129	209
Capacity utilization (%)	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	98	86
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	107	188
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	210	271
Demand / Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	203	411

68. From the above, the Authority notes that:

- The domestic industry has increased their capacity throughout the injury investigation period to cater to the increasing demand of India. Capacity utilization of the domestic industry was \*\*\* % of the installed capacity during the period of investigation. This implies that around \*\*\* % of the installed capacity remained unutilized, despite significant increase in the demand of the subject goods.
- The domestic sales of the domestic industry are negligible (around \*\*\* %), in comparison to the total demand of the subject goods.
- As per the data available on record, other producers have combined capacity of \*\*\* MT. The total available capacity in India along with applicant industry is as follows:

Particulars	Capacity	Sales	Imports - Total	Total Demand
Production (MT)				
Applicant (MT)	***	***		
Gobind Glass & Industries Ltd. (MT)	***	***		
Triveni Renewables Private Ltd. (MT)	***	***		
Vishakha Glass Pvt. Ltd. (MT)	***	***		
Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd. (MT)	***			
Emerge Glass (MT)	***			
Total (MT)	***	***	795,555	***

d. From the above, it is noted that currently Indian producers have around \*\*\* % of the Indian demand. Moreover, as submitted by the Indian industries, some of the other producers have delayed the installation of their machineries because of influx of imports from China, post expiry of anti-dumping-duties.

### ii) Market Share

69. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in the table below:

Market share	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Domestic industry Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	107	188
Sales of Other Indian Producers	MT	0	0	0	***
Trend	Indexed	-	-	-	100
Total Indian Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	107	225
Imports from Subject country	MT	656	78,093	1,03,277	1,19,285
Trend	Indexed	100	11,912	15,753	18,195
Imports from Other Countries	MT	1,58,144	1,20,343	2,92,247	6,76,269
Trend	Indexed	100	76	185	428
Total Imports	MT	1,58,799	1,98,436	3,95,524	7,95,555
Trend	Indexed	100	125	249	501
Demand in India	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	203	411
<b>Market Share</b>					
Domestic industry	%-	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	53	46
Other Producers Industry	%-				***
Trend	Indexed				100
Indian producers	%-	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	53	55

Market share	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject imports	%-	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	9,950	7,766	4,429
Other Country Imports	%-	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	91	104

70. It is noted that despite having sufficient capacity of approximately \*\*\* % of the demand, the share of the domestic industry in the Indian market is only \*\*\* %.

**(iii) Inventories**

71. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	289	405

72. It is noted that the average inventories of the domestic industry have increased throughout the injury investigation period. Further, it is seen that the average inventory was highest during the period of investigation.

**(iv) Profit/loss, cash profit and return on capital invested.**

73. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales (domestic)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	119	105
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	111	93
Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-56	-236	-269
Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-61	-253	-505
Cash Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-43	-316	-633
Return of investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-83	-269	-453

74. From the above, the Authority notes that:

- The selling price of the domestic industry has declined in the POI vis-à-vis year 2021-22 and 2022-23
- During the POI, the cost of the domestic industry declined, however, the decline in selling price was steeper. The applicant has submitted that this has further worsened their position.
- The applicant has incurred losses and cash losses and is suffering negative return on investment during the period of investigation.

**(v) Employment, wages and productivity.**

75. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	172	177
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	118	115
Salaries & Wages	Rs/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	68	65
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	129	209
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	75	118

76. It is noted that the number of employees increased throughout the injury investigation period, as the domestic industry has increased the capacity to cater to the increased demand. It is further noted that the productivity has also increased which shows that there is no negative impact of increase in the number of employees.

77. The salary paid to the employees decreased by around \*\*\* % i.e., from 100 indexed points in the base year to \*\*\* indexed points in the period of investigation, which, as submitted by the domestic industry indicates the negative impact of subsidy on it.

**(vi) Growth.**

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Demand – MT	%	-	***	***	***
Production – MT	%	-	***	***	***
Domestic Sales - MT	%	-	***	***	***
Market share %	%	-	***	***	***
Domestic sales - Rs/MT	%	-	***	***	***
Profit / Loss - Rs/MT	%	-	***	***	***
Cash Profits - Rs/MT	%	-	***	***	***
Return on capital employed %	%	-	***	***	***

78. From the above, the Authority notes that the demand of the subject goods increased substantially during the injury investigation period. However, the domestic sales and market share have not increased in the same ratio. Profitability, cash flow and return on capital employed were significantly negative in the period of investigation which is reflective of the deterioration of performance of the domestic industry during the period of investigation.

**(vii) Ability to raise capital investment.**

79. The applicant has submitted that it has incurred steep losses and is facing negative returns. The Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBIDTA) has continuously deteriorated over the injury period and remained negative. The applicant has further submitted that the negative EBIDTA shows that the domestic industry is not earning enough to even meet its present obligations and there is a negative impact on the ability to raise capital investment.

**(h) Margin of subsidy.**

80. The margin of subsidy is an indicator of the extent to which the subsidized imports can cause injury to the domestic industry. The subsidy margin is positive and significant for Vietnam.

**Factors affecting prices of the domestic industry.**

81. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices to a remunerative level during the period of investigation. The imports have forced the domestic industry to sell the goods below cost. Further, the low-priced imports have also resulted in low market share, and underutilized capacity of the Domestic Industry. Thus, the subject imports from Vietnam have adversely affected the prices of the domestic industry.

**CONCLUSION ON MATERIAL INJURY**

82. After examining the volume and price effects of imports of subject goods from the subject country and its impact on the domestic industry, the Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject country increased significantly during the period of investigation as compared to the base year in absolute terms. With regard to price effect on account of imports of subject goods from subject country, it is noted that imports of the subject goods from subject country is suppressing / depressing the prices of domestic industry. Comparison of the landed values with the non-injurious prices of the Domestic Industry also reveals injury to the Domestic Industry. With regard to consequent impact of the subsidized imports on the domestic industry, it is concluded that the performance remained negative in respect of profit, return on investment and cash flow. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation

**H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS.**

83. Having examined the existence of injury, volume and price effect of subsidized imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the subsidized imports, as listed under the Rules.

**a. Volume and price of imports from third countries.**

84. It is noted that imports from non-subject country are negligible by the way of volume except China. It is noted that anti-dumping investigations are underway with respect to China. Therefore, the injury caused cannot be attributed to the third countries.

**b. Contraction in the demand**

85. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased throughout the injury investigation period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

**c. Pattern of consumption**

86. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

**d. Conditions of competition**

87. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.

**e. Developments in technology**

88. The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

**f. Export performance of the domestic industry**

89. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

### **Factors establishing causal link**

90. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- i. imports have increased in absolute terms and have remained significant in relative terms. Imports have increased despite increase in capacity and production in the country.
- ii. Landed price of the subject imports is below the selling price of the domestic industry and also below the cost of sales in the POI and has caused price suppression.
- iii. The market share of the domestic industry has significantly declined during the injury period.
- iv. Inventories of the domestic industry has been on the rise and has increased significantly in the POI.
- v. The domestic industry's profitability and return on capital employed has been adversely affected

91. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increased subsidised imports of the PUC into India from the subject countries. There exists a causal relation between the increase in subsidised imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and the material injury suffered by the domestic industry.

### **I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.**

92. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net axed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

93. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

94. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Producer	Landed value (USD/MT)	NIP (USD/MT)	Injury margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin
					(Range)
<b>Vietnam</b>					
Flat (Vietnam) Co., Ltd/ Flat (Hong Kong) Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
Others	***	***	***	***	50-60

### **J. ISSUES OF THE INDIAN INDUSTRY**

#### **J.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.**

95. The other interested parties have made following submissions with regard to the Indian industry's interest.

- a. Anti-subsidy duties on solar glass will significantly raise production costs for solar module manufacturers, particularly those relying on imported textured tempered glass for advanced photovoltaic technologies. This increase in cost will not only affect India's solar competitiveness but also slow down progress toward achieving national climate goals and renewable energy targets.
- b. The downstream industries argue that higher costs could lead to reduced adoption of solar energy due to less competitive pricing in both domestic and global markets, further disadvantaging India in its green energy initiatives.

- c. It was also submitted that the impact of duties is much more than what is indicated by the Authority in the provisional findings. According to the calculation submitted by them the impact of the duties would be around 3% from Vietnam and 6% from China.

### **J.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.**

96. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. The domestic industry has the capacity to cater around \*\*\* % the Indian demand.
- b. It is further noted that apart from the domestic industry, five more producers have set up plants for production of the subject goods with the intention of making India self-sufficient.
- c. If the current situation continues, the domestic industry will have no option but to permanently shut down its operations and India and it will once again become import dependent.
- d. In light of the widening trade deficit, it is important to rely more on domestic production capacities. Imposition of duties would allow conservation of the outgoing foreign exchange favoring the balance of payment account
- e. The impact of the imposition of anti-subsidy duty on subject goods will be negligible as compared to the cost of the solar module.
- f. Since there are already six players in the market and few more are to commence production, this would ensure that there is no monopoly in India and that the users would have enough sources in the domestic market as well.
- g. The product under consideration can be imported at fair prices from other sources also and, therefore, there would be no adverse impact on users.
- h. Domestic Industry submitted that Solar Photovoltaic Panels/ module manufacturers have 40% BCD and support of Approved List of Module Manufacturers (ALMM). This gives protection to the solar module manufacturers from low priced imports from China and other countries. It is also important to state that the subject goods constitute very small portion of the cost of solar module. Therefore, there would be no serious adverse impact of the anti-subsidy duties on the end product.
- i. In relation to impact of duties, it is submitted that the impact of duties on subject goods would be minuscule on module cost based on prevailing costs in the POI. In terms of impact on the per unit cost of electricity, the impact of duties on subject goods would be much less. Thus, the impact the anti-subsidy duties on the subject goods is either non-existent or very insignificant.
- j. Domestic Industry has also submitted that subsidy duties would significantly contribute towards creating a local supply chain for a critical component and also to achieve the larger goal of "Atmanirbhar Bharat" in this strategically important sector besides saving the foreign exchange outgo and create jobs. Therefore, the duties are in interest of Indian users.

### **J.3 Examination by the Authority.**

97. The Authority underscores that the primary objective of anti-subsidy duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of subsidy, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-subsidy measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is based on a detailed analysis regarding subsidy injury and the causal link between the two and is a mechanism to ensure a level playing. The Authority acknowledges that the presence of anti-subsidy duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-subsidy measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through subsidy practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-subsidy duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

98. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to furnish pertinent information related to the ongoing investigation including the possible effect of anti-subsidy duty on their operations.

99. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-subsidy

duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-subsidy duty.

100. The Authority notes that no user of the subject goods has stepped forward to participate before the Authority or furnished a response to the Economic Interest Questionnaire. Furthermore, no party has presented any evidence to indicate the adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and participation of the stakeholders underscores the Authority's position and reinforces the necessity of anti-subsidy measures to ensure fair trade practices.

101. The Authority, however, notes that the domestic industry, based on the current market prices, has provided an estimate of the possible impact of the anti-subsidy duties on the end consumers in the following table:

Particulars	Reference	UoM	Amount
Price of 540 Wp solar module based on MIC) solar cells	A	Rs./Module	***
Subject goods used in 540 Wp solar module based on M10 solar cells	B	Kgs./Module	***
Price of Subject goods – Coated	C	Rs./Kg.	***
Costs of subject goods build in 540 Wp solar module based on M10 solar cells	D=C*B	Rs/MT	***
% cost of subject goods in Module	E=D/A	%	***
Additional cost on Module due to 5% anti-subsidy duties on subject goods	F=D*5%	Rs/MT	***
Total cost of subject goods in module adding anti-subsidy duties	G=D+F	Rs/MT	***
% cost of subject goods in Module	H=G/A	%	***
Additional impact per Solar Module due to anti-subsidy duties	I=F/A	%	<b>0.50%</b>

102. From the above submission the Authority notes that the impact of the anti-subsidy duties on the end consumers will be insignificant.

103. In relation to the high impact of the duties on users, it is noted that the users have not provided any evidence as how it will impact their financial performance or the impact of duties on the final consumer. No analysis / data / working was also provided to substantiate their claim. Further, user association merely substituted lower landed value in the Table to show higher impact, but none of them showed impact based on the prices prevailing during injury investigation period.

104. The Authority notes that anti-subsidy duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product.

## K. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

105. The Authority has examined all post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

### Submissions made by the other interested parties

106. The submissions made by the other interested parties are as under:

- In relation to computation of subsidy margins in respect of Income Tax Exemption, the exporter has requested that the Authority to use benchmark tax rate as 10% instead of 20%, which has been considered by the Authority. They have therefore, requested the Authority to kindly correct the subsidy margin considering 10% as benefit available under this scheme.
- In related to land rent related subsidy, it has been submitted by the interested party that the Authority should drop any subsidy margin for this scheme, as the exporter is paying higher rent as compared to the rent prevailing in the market.
- Interested parties have also contended that the domestic industry, being the sole manufacturer of the subject goods, cannot meet India's total demand, forcing reliance on imports. Granting protection to this monopoly

would raise costs for solar panel producers, reduce competitiveness, and hinder India's net-zero emissions goal by disproportionately benefiting a single producer i.e. Borosil Renewables Energy Limited.

- d. The producers/exporters have argued that imposing duties on textured tempered glass from Vietnam would harm India's renewable energy goals. As textured tempered glass is a key component of solar panels, the duties would increase costs, making solar projects less affordable and competitive, and undermine efforts to meet India's renewable energy targets. Therefore, they claim such duties are not justified.
- e. It has been submitted that India does not have an established ecosystem for manufacturing the PUC and satisfying the increasing demand for the same in India and therefore, the duties will create monopoly in the market. The duties will further lead to demand and supply gap, due to which imports are necessary in India.
- f. There is no causal link between imports and domestic industry's financial struggles. It is further stressed that due to overcapacity and interest costs domestic industry is suffering injury.
- g. It has also been submitted that BRL has not adequately addressed the quality complaints from users and therefore, the Authority should address them in final findings.
- h. Interested parties have also submitted that the Domestic Industry losses are not due to imports from subject countries but other factors such as expansion-related financial burdens, demand-supply gap in domestic production and high depreciation and interest costs
- i. High return on capital employed (22%) has been considered by the Authority while calculating NIP and due to this inflated NIP, injury margins are also very high leading to high injury margin and duties for users.

#### **Submissions of the Domestic Industry:**

107. The submissions made by the Domestic Industry are as under:

- a. Domestic Industry has requested the Authority to share detailed calculations of the Non-Injurious Price (NIP) and consider the NIP based on the verified information and also to give due cognizance to the information submitted during verification and accordingly, modify injury margin in the final findings.
- b. It has been submitted that certain importers, with the help of exporters, are clearing the subject goods under the name "heat strengthened solar glass" instead of "textured tempered glass" to evade anti-dumping duties. Domestic industry believes that this change in description is intended to bypass the duties. Therefore, the Domestic Industry has requested the Authority to clarify that "heat strengthened solar glass" is also covered under the product under consideration in the final findings, to ensure that no undue advantage is taken by importers due to the altered description.
- c. In relation to quality concerns, the Domestic Industry asserts that its products are at par with imports and that minor quality issues are a normal business occurrence. They have also submitted that from the data on record, it is very clear that the total quality claims received by the Domestic Industry during injury investigation period or post POI is very minuscule.

#### **Examination by the Authority**

- 108. The Authority observes that the majority of the submissions made by interested parties have already been considered and appropriately dealt with in the disclosure statement. These, along with any additional submissions, have been comprehensively addressed in the relevant sections of these final findings. The concerns raised by the Domestic Industry have also been examined and duly responded to within the appropriate sections of these findings.
- 109. With regards to submissions of domestic industry to share detailed calculations of NIP, and consider the NIP based on the verified information, it is reiterated that the Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. Further detailed calculations have been shared with the domestic industry at the time of issuance of disclosure statement.
- 110. In relation to Income Tax Exemption scheme, it is noted that the Authority has considered the tax rate from the verified documents and available decree and annual accounts/income tax return copy on record. In view thereof, the subsidy margin computed by the Authority considering tax rate as 20% for this scheme is correct and justified.
- 111. In relation to land rent exemption scheme, it is noted that in the absence of submission of any information by GOV in its questionnaire response on the complete price fixation mechanism and the nature of its agreement with other agencies, the Authority cannot conclude that the contracted amount is based on the market rates. In view therefore, the Authority has considered that this program provides financial contribution in the form

of provision of goods or services at less than adequate remuneration and computed subsidy margin based on facts available in terms of Rule 7(8) of subsidy Rules.

112. With regard to creation of monopoly and reliance on imports due to demand and supply gap, it is noted that the issue of monopoly does not arise since there are several other domestic producers who have already established the manufacturing units for production of subject goods in India. Additionally, the imported subject goods are always available in the Indian market at unsubsidized price.

113. The Authority notes that anti subsidy duties are imposed only after the outcome of a thorough investigation which establishes that subsidized imports are causing material injury to the domestic industry. The objective is to counteract the unfair pricing practices of foreign exporters and ensure a level playing field, rather than granting undue protection to domestic producers. Moreover, anti-subsidy investigations consider the presence of multiple domestic producers, as in the subject investigation, and assess the competitive dynamics within the market. The duties are designed to prevent injury to the domestic industry without unduly restricting imports, ensuring that fair-priced imports remain available to consumers. Additionally, anti-subsidy measures are subject to periodic review, allowing for their withdrawal if circumstances change. Thus, these duties do not create monopolies but rather uphold the principles of fair competition in international trade, in line with the provisions of the WTO Agreement.

114. In relation to impact of duties on India's renewable energy goals, the Authority has already noted in the appropriate paragraph of the final findings that the impact of anti-subsidy duty is not significant and hence it will not have an adverse impact on Indian Solar mission. The level playing field will encourage the development of entire value chain in the country and thus ensure proper ecosystem for manufacturing of the PUC.

115. In relation to demand and supply gap, it is noted that, with the present capacity available with the domestic producers, it can cater to \*\*\*% of the demand in India. The presence of anti-subsidy duties will not stop the imports but will only provide a level playing field and promote fair competition in the market.

116. In relation to impact of overcapacity built by domestic industry and its impact on financial performance, it is noted that depreciation and finance cost constitutes \*\*\*% of the total cost. In view thereof, it is clear that such small percentage cannot be held responsible for the significant injury and losses of the domestic industry.

117. In relation to quality concerns, the Authority has verified the compensation made in lieu of quality concerns and net of sales return over the injury investigation period and found the same to be inconsequential, as can be seen from the Table below.

Year Wise	Total Sales (Rs. In Lakhs)	Quality Claim (Rs. In Lakhs)	Sales return (Net of Resales) (Rs. In Lakhs)	Total Claim (Rs. In Lakhs)	% (Total Claim / Total sales)	Range (%)
FY 2020-21	***	***	***	***	***	0-1
FY 2021-22	***	***	***	***	***	0-1
FY 2022-23	***	***	***	***	***	0-1
POI - CY 2023	***	***	***	***	***	0-1
CY 2024	***	***	***	***	***	0-1

118. The Authority acknowledges the concern of the domestic industry regarding the description change from "textured tempered glass" to "heat strengthened solar glass." The matter has been duly considered, and appropriate clarifications have been incorporated in the final findings to prevent any evasion of anti-dumping duties.

## L. CONCLUSIONS

119. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the subsidy, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

a. The product under consideration for the present investigation is Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated. The PUC is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass,

high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass, and heat strengthened glass.

- b. The product produced by the applicant is a like article to the imported product.
- c. Borosil Renewable Limited, constitutes 'the domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3).
- d. Considering the benefit availed by the producers / exporters of the product under consideration in Vietnam, the subsidy margins for the product under consideration from Vietnam has been determined, and the margins are positive.
- e. The examination of the imports of the product under consideration shows that the volume of subsidized imports from the subject country have increased manifold in the period of investigation. The imports have increased in both absolute terms and in relation to production and consumption.
- f. The import price is below the selling price of the domestic industry resulting in price undercutting.
- g. The import price has not moved in line with the cost of production which has prevented the domestic industry from increasing its prices to the appropriate/desired levels.
- h. The domestic industry is suffering from financial losses, cash losses and a negative return on capital employed.
- i. The Authority has examined the submissions made by other interested parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that material injury suffered by the domestic industry is caused by the subsidized imports from the subject country.
- j. Imposition of anti-subsidy duty would not affect the availability of the product to the customers. The imports of the product under consideration will continue to happen at fair prices.
- k. The Authority has quantified the impact of anti-subsidy duty on the users. It is seen that the impact of the recommended measures on the eventual end consumers will be insignificant.

## **M. RECOMMENDATIONS**

- 120. It is noted that the Authority in the parallel anti-dumping investigation has recommended anti-dumping duties on the same product under consideration vide final findings F. No. 6/29/2023-DGTR dated 10<sup>th</sup> February, 2025. The Authority had recommended preliminary findings on 05.11.2024, which was accepted by Ministry of Finance vide notification No. 26/2024-Customs (ADD) dated 04.12.2024.
- 121. It is further noted that preliminary anti-dumping duty was recommended on reference-price based on the factual matrix of the case and in the final findings also, the Authority has recommended anti-dumping duties based on reference price only. Therefore, now the anti-dumping duty is payable if the subject goods will be landing below the reference price notified vide final findings F. No. 6/29/2023-DGTR dated 10<sup>th</sup> February, 2025 and the amount of ADD would be to the extent of difference between the landed value of subject goods, and the reference price indicated in column 7 of the duty table of the above Notification provided the landed value is less than reference price in that duty table.
- 122. In terms of Section 9B(1)(a) of the Act, no article shall be subject to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization. Considering the above provision, the Authority has taken due care that the product under consideration should not be subject to both anti-dumping and export subsidy. In this context, it is important to highlight that the subsidy margin quantified by the Authority in paragraph 50 pertains to subsidies other than export subsidies. Therefore, there will be no double protection to the Domestic Industry and will cause no prejudice to any interested party whatsoever. Besides, it is noted that since the POI of anti-dumping and countervailing investigation is same, the Authority has taken due care of the fact that total duty on account of dumping margin and subsidy margin together should not exceed the level of injury margin calculated for the POI. The same is also reflected in the Table below:

Producer	Dumping Margin	Dumping Margin	Subsidy Margin	Subsidy Margin	Dumping Margin + Subsidy Margin	Injury Margin	Injury Margin	CIF Value
	USD/MT	%	USD/MT	%	USD/MT	USD/MT	%	USD/MT
Flat (Vietnam) Co Ltd	***	***	***	***	***	***	***	***
Range	-	30-40	-	0-10	-	-	50-60	-
All Others	***	***	***	***	***	***	***	***
Range	-	80-90	-	0-10	-	-	50-60	-

123. From the above, it is clear that the injury margin which is same for both the anti-dumping investigation and anti-subsidy investigation because of same POI, is higher than the sum of both dumping margin and subsidy margin taken together for the co-operating exporter /producer i.e., Flat (Vietnam) Co Ltd. It is further noted that for all the other producers / exporters of the subject goods from Vietnam, the anti-dumping duties are already recommended up to the level of injury margin and therefore, no additional anti subsidy duty will be levied.

124. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

125. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury so determined in these findings for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the subsidized imports on the domestic industry. Taking into account factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-subsidy duties. Accordingly, reference form of anti-subsidy duty is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country, for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Reference price in the present investigation is determined by adding lower of subsidy margin or injury margin to the reference price recommended by the authority in anti-dumping investigation. The anti-subsidy/countervailing duty is recommended as the difference between the landed value of the subject goods as described in Col.3 of the duty table below and the reference price amount indicated in Col.7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col.7. If the landed value is more than the value indicated in Col 7, the anti-subsidy duty will not be applicable. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

#### DUTY TABLE

S No.	Heading/ Sub- heading	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541*	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass**	Vietnam	Vietnam	Flat (Vietnam) Co., Ltd	593	MT	USD

S No.	Heading/ Sub- heading	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
2	-do-	-do-	Vietnam	All countries including Vietnam	Any Producer other than producer mentioned in serial number 1	664	MT	USD
3	-do-	-do-	All countries other than Vietnam	Vietnam	Any	664	MT	USD

\*The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

\*\*Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated. The product is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass and heat strengthened glass.

Note 1: It may be noted that for Serial No. 1 to 3 above, the anti-dumping duties are already recommended by DGTR vide final findings F. No. 6/29/2023-DGTR dated 10<sup>th</sup> February, 2025 for the subject goods, therefore, the amount of duty to be collected based on the reference price specified under column 7 of the duty table above shall stand reduced by the amount paid by way of anti-dumping duty.

To clarify how the both anti-dumping and anti-subsidy duty will operate, illustrations are provided below:

**Examples:**

**Scenario: When both ADD (reference form of duty) and CVD (reference form of duty) are applicable**

- The reference-based duty for the participating producer is USD 593/MT. If the landed value of exports to India by Flat (Vietnam) Co., Ltd for PUC is USD 500/MT, the anti-dumping duty would be USD **70** / MT (USD 570/MT minus USD 500 / MT) and countervailing duty will be USD **23** / MT (593-500-70).
- The reference-based duty for the participating producer is USD 593/MT. If the landed value of exports to India by Flat (Vietnam) Co., Ltd for PUC is USD 580/MT, the anti-dumping duty would be USD **Nil** / MT (USD 570/MT minus USD 580/ MT) and countervailing duty will be USD **13** / MT (593-580).
- The reference-based duty for the participating producer is USD 593/MT. If the landed value of exports to India by Flat (Vietnam) Co., Ltd for PUC is USD 600/MT, the anti-dumping duty would be USD **Nil** / MT (USD 570/MT minus USD 600/ MT) and countervailing duty will also be USD **Nil** / MT (593-600).

**N. FURTHER PROCEDURE**

126. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority